राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

दिव्य दिनकर

एक निडर सच का दर्पण

रांची और पटना से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 12 अकं :223 रांची (झारखंड) सोमवार,26 मई 2025 पेज - 08 मूल्य: 2 RNI NO- JHAHIN/2013/54373

ऐतिहासिक उपलब्धि : संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया

एजेंसी

नई दिल्ली । नई दिल्ली। भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) को सफलतापूर्वक फतह करने का कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इस दल में भारतीय सेना के जवान, प्रशिक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों – जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग – के प्रशिक्षकों की संयुक्त पर्वतारोहण टीम ने 23 मई 2025 को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) को सफलतापूर्वक फतह कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अभियान 26 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। 26 मार्च को नई दिल्ली से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा हरी झंडी दिखाकर पर्वतारोहियों के दल को रवाना किया गया था। इस दल का नेतृत्व नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्राचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के प्राचार्य कर्नल हेम

चंद्र सिंह ने किया। इस दल में पांच विशेषज्ञ प्रशिक्षक शामिल थे। प्रशिक्षकों में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के हवलदार राजेन्द्र मुखिया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के राकेश सिंह राणा, सूबेदार बहादुर पाहन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पासंग तेनजिंग शेर्पा और हवलदार थुप्स्तन त्सेवांग शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम ने एवरेस्ट पर चढ़ाई से पूर्व, 18 अप्रैल 2025 को अपनी अनुकूलन प्रक्रिया के तहत माउंट लोबुचे (6,119 मीटर) को भी सफलतापूर्वक आरोहित किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के इस चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान पर्वतारोहियों ने भीषण मौसम और अत्यधिक ऊंचाई जैसी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। इस दौरान पूरी टीम ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अनुकरणीय टीम भावना का परिचय दिया। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस उपलब्धि के साथ पर्वतारोहियों की इस टीम ने भारत के पर्वतारोहण इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। टीम अब सुरक्षित रूप से एवरेस्ट बेस कैंप से उतरकर काठमांडू की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि इसी माह राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के पर्वतारोहण दल ने 18 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इसके बाद टीम सुरक्षित रूप से एवरेस्ट बेस कैंप पर लौट आई। वह ऐतिहासिक उपलब्धि थी और एनसीसी अभियान दल द्वारा माउंट एवरेस्ट पर तीसरी सफल चढ़ाई थी।

लालू यादव का बड़ा फैसला : तेज प्रताप यादव आरजेडी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित

एजेंसी

पटना। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह फैसला राजनीतिक हलकों में गहरी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसे लालू परिवार के भीतर बढ़ती कलह और पार्टी की आंतरिक संरचना पर इसके संभावित प्रभावों के रूप में देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने लिखा, 'निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।' यह निष्कासन तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों और पार्टी कार्यक्रमों में उनके अनियमित व्यवहार के बाद आया है, जिसे अक्सर पार्टी नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला माना जाता रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब RJD बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने में लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव का यह कदम परिवार के भीतर अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की छवि को धूमिल होने से बचाने का प्रयास है। यह फैसला दिखाता है कि लालू प्रसाद, भले ही स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर हों, लेकिन पार्टी और परिवार पर उनका नियंत्रण अभी भी बरकरार है। इस निष्कासन से RJD के भीतर शक्ति संतुलन और तेजस्वी यादव की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, जिन्हें लालू का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

सीएम सुक्खू ने वित्त आयोग के अध्यक्ष से की भेंट, हिमाचल प्रदेश के लिए मांगी अधिक निधि

नई दिल्ली/शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद राज्य सरकार के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष प्रस्तुति दी और राज्य की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। इसी कारण उन्हें उनका उचित हक मिलना चाहिए। प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य की सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग भी

की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के कारण राज्य को नुकसान हुआ है और इसके लिए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि धीरे-धीरे समाप्त किया जाए। मुलाकात के दौरान डॉ. पनगढ़िया ने आश्वासन दिया कि आयोग राज्य के आग्रह पर विचार करेगा।

पीएम मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों के मन की बात करते हैं : अनिल विज

अंबाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम के 122वें एपिसोड पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में सिर्फ अपने मन की नहीं बल्कि देशवासियों के मन की बात करते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने मन की बात लोगों के साथ करते हैं। वर्तमान में जो ताजा मुद्दा होता है उससे देशवासियों को रूबरू करवाते हैं। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में पराक्रम दिखाया, वह काबिले तारीफ है। इसके अलावा, नक्सली मूवमेंट, पर्यावरण संरक्षण, गुजरात के गिर में शेरों के संरक्षण और संख्या पर

उन्होंने विस्तार से बात की। इसके अलावा उन्होंने ड्रोन दीदी से लाभ उठा रही महिलाओं के बारे में जिक्र किया। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में इन चीजों को इसलिए उठाते हैं ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो। विकसित राष्ट्र के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाक के सीजफायर पर विपक्ष के आरोपों पर अनिल विज ने कहा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का सीजफायर हो गया। लेकिन, जुबानी गोलाबारी हो रही है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे मिलेंगे। सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर राजनीति न करें।

पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को 'वोकल फॉर लोकल' से जोड़ा

▸▸ कहा- 'देश में बनी चीजों को प्राथमिकता दें'

'हमें आतंकवाद को खत्म करना है।'

एजेंसी

नई दिल्ली । 'मन की बात' के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प भी था। पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्निशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में 'वोकल फॉर लोकल' को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती हैं। एक मां-बाप ने कहा कि अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने

खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। 'प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ परिवारों ने शपथ ली है कि हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने 'वेड इन इंडिया' का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है कि अब जो भी गिफ्ट देंगे, वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों की सराहना करते हुए कहा, साथियों, यही तो है, भारत की असली ताकत 'जन-मन का जुड़ाव, जन-भागीदारी'। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए, इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो, देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम, भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। इससे पहले उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए देशवासियों की सराहना की। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। पीएम मोदी ने 'मन की बात' को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। साथियों, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ, हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, वो अद्भुत है।

पत्नी अनुष्का संग अयोध्या पहुंचे विराट कोहली, रामलला के किए दर्शन

एजेंसी

अयोध्या। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संग अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला के दर्शन किए और फिर हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर पर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट इससे पहले पत्नी संग वृंदावन भी पहुंचे थे और वहां संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर उनसे आशीर्वाद लिया था। हनुमानगढ़ी में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास ने दर्शन-पूजन कराया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें फूल माला पहनाया और टीका लगाया। विराट-अनुष्का के पूजा-अर्चना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दर्शन के दौरान स्टार कपल ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। इसके अलावा कपल ने हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी व संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दत्त से भी मुलाकात की। फिलहाल विराट कोहली इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में व्यस्त हैं। उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। टीम को अपना आखिरी लीग मैच लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मंगलवार यानी 27 मई को खेलना है। यह मैच

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में है।कोहली का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन आईपीएल के मौजूदा सीजन में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। उन?होंने आईपीएल 2025 में 12 मैचों में 7 अर्धशतकों की मदद से 548 रन बनाए हैं। उनका औसत 60.89 का रहा है। वह अपनी टीम को पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीताने की कोशिश करेंगे।

कोच्चि के पास समुद्र में डूबा लाइबेरियाई कंटेनर पोत, सभी 24 सदस्य बचाए गए

'किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए भारतीय जहाज पूरी तरह तैयार हैं। '

एजेंसी

कोच्चि। कोच्चि से लगभग 38 समुद्री मील दूर रविवार को लाइबेरियाई कंटेनर पोत एल्सा-3 बाढ़ के कारण गहरे पानी में डूब गया, लेकिन भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। समुद्र में डूबे जहाज से किसी भी तेल या रासायनिक रिसाव पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए भारतीय जहाज पूरी तरह तैयार हैं। आईसीजी के कमांडर अमित उनियाल ने बताया कि 184 मीटर लंबा लाइबेरियाई कंटेनर जहाज एल्सा-3 तिरुवनंतपुरम के पास विझिनजाम बंदरगाह से 23 मई को कोच्चि बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था। कोच्चि के रास्ते में जहाज के स्टारबोर्ड की तरफ 26 डिग्री का झुकाव होने पर चालक दल

के 09 सदस्य लाइफ राफ्ट में चले गए। जहाज के कप्तान, मुख्य अभियंता और इंजीनियर बचाव कार्यों के लिए संकटग्रस्त जहाज पर सवार थे। भारतीय तटरक्षक बल को 24 मई को लगभग 13.25 बजे कोच्चि से करीब 38 समुद्री मील दूर लाइबेरियाई ध्वज वाले कंटेनर पोत एमएससी ईएलएसए 3 पर संकट की स्थिति के बारे में सूचना मिली

दरअसल, शिपिंग कंपनी पोत के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ थी और उसने पोत पर सवार 24 चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईसीजी से सहायता मांगी। इस पर कोच्चि स्थित आईसीजी जिला मुख्यालय के अंतर्गत समुद्री बचाव उपकेंद्र (एमआरएससी) ने आईसीजी डोर्नियर विमान को हवाई निगरानी करने और जहाज से संपर्क स्थापित करने का काम सौंपा। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए विमान ने जहाज का पता लगाया। पानी में दो लाइफ राफ्ट दिखाई दीं, जिनमें क्रमशः 05 और 04 लोग जीवित लोग सवार थे। संकटग्रस्त स्थान के पास तैरते हुए कुछ कंटेनरों की भी पहचान की गई।

माओवादी हिंसा के खिलाफ सफलता के बाद प्रभावित जगहों पर सामान्य सुविधाएं पहुंचने लगीं-मोदी

● **काटेझरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है।**

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माओवादी हिंसा के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की सफलता बाद अब हिंसा से प्रभावित जगहों पर सामान्य सुविधाएं पहुंचने लगीं हैं और दंतेवाड़ा जैसे जिले खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल कर रहे हैं। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 122वें अंक में कहा, 'बस से कहीं आना-जाना कितनी सामान्य बात है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढ़ोल-नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों

बस नहीं चल पाई थी। क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है, काटेझरी। काटेझरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा।' श्री मोदी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विज्ञान प्रयोगशाला पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में विज्ञान के प्रति लगाव है। वो खेलों में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे यह जानकार भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं।

गुजरात, केरल और बंगाल समेत चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान

23 जून को आएंगे नतीजे

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव की घोषणा कर दी है। 19 जून को मतदान होगा, जबकि 23 जून को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर चार राज्यों केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की है। ईसीआई ने बताया कि गुजरात के कादी (एससी) और विसावदर विधानसभा, केरल की निलंबूर, पंजाब की लुधियाना और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 26 मई 2025 (सोमवार) को राजपत्र

अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 जून (सोमवार) तय की गई है, जबकि 3 जून (मंगलवार) को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 5 जून (गुरुवार) तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 19 जून 2025 (गुरुवार) को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद 23 जून (सोमवार) को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, 25 जून 2025 (बुधवार) तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। यह उपचुनाव संबंधित क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। बता दें कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी जगहों पर अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। बंगाल में टीएमसी, गुजरात में भाजपा, पंजाब में 'आप' और केरल में सीपीआई (एम) की सरकार है।

चुनाव- तारीख और दिन

राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख: 26 मई 2025 (सोमवार)
नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख: 2 जून 2025 (सोमवार)
नामांकन पत्रों की जांच की तारीख: 3 जून 2025 (मंगलवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख: 5 जून 2025 (गुरुवार)
मतदान की तारीख: 19 जून 2025 (गुरुवार)
वोटों की गिनती की तारीख: 23 जून 2025 (सोमवार)
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख: 25 जून 2025 (बुधवार)

रगों में सिंदूर की बात करने वाले मोदी बदजुबान नेताओं पर नहीं करते कार्रवाई-खड़गे

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और मंत्री पहलगाम मुद्दे पर सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खामोश हैं। श्री खड़गे ने कहा 'भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और बहादुर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान से एक बार फिर आरएसएस भाजपा की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जाँबाज़ सेना का अपमान किया पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए।' उन्होंने कहा 'जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफ़िसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था तब भी मोदी जी चुप थे। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा

है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इन बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए।' कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा नेता लगातार सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं जो उनकी ओछी मानसिकता को उजागर करते हैं।

'ऑपरेशन सिंदूर' का श्रेय मोदी को देने की होड़ में भाजपा करवा रही है सेना का अपमान : कांग्रेस

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और उसके नेता नैतिकता को ताक पर रखकर 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देने की होड़ में बहादुर सेना तथा हमले के पीड़ितों को अपमानित कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई करवाई नहीं हो रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा नेता एक के बाद एक पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं लेकिन श्री मोदी और भाजपा नेतृत्व उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।सुश्री लांबा ने कहा, भाजपा नेता 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का श्रेय श्री मोदी को देते हुए उनका गुणगान करके सेना और पीड़ितों को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व से आदेश पाकर वे जहां मौका मिले ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और इस होड़ में भाजपा नेताओं की जुबान बिगड़ गई है।' महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,÷श्रेय देने की होड़ में भाजपा यानी बदजुबान पार्टी के नेता संयम खोते हुए अपनी भाषा भूल गए और सेना का अपमान करने लगे। इस कड़ी में बदजुबान पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सेना के साथ शहीदों और उनके परिवार वालों का भी अपमान किया। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की पत्नियों को अपमानित करते हैं। भाजपा सांसद जांगड़ा का कहना है- पहलगाम हमले में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। इसलिए हाथ जोड़ रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं।

संक्षिप्त समाचार

डीसी ने वायरल फीवर की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक की

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़;बरसात के दिनों में डेंगू, टायफाइड एवं मलेरिया जैसे बिमारियों की रोकथाम के लिए उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला टास्क फोर्स के साथ बैठक किया। सतर्कता बरतने एवं इसके लक्षणों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने पर बल दिया गया। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत कार्यतालिका तैयार किया जाए, जिससे वर्णित विषयों पर प्रभावी नियंत्रण ससमय की जा सके बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर परिषद को नियमित रूप से फॉगिंग, एंटी लार्वल स्प्रे, नालों की सफाई तथा जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें दूर करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आमजन को जागरूक करने हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के टीम से कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जन-जागरूकता लायें ताकि जमीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़े और वे स्वयं भी डेंगू रोकथाम के उपायों में भागीदार बनें। जिला मलेरिया पदाधिकारी द्वारा डेंगू के लक्षण, परीक्षण की व्यवस्था, इलाज की प्रक्रिया एवं रोकथाम संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि समय रहते कदम उठाए जाने से डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई ,21 बोटा सेमल लकड़ी के साथ एक पिकअप वैन जब्त, एक गिरफ्तार

साहिबगंजः वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 बोटा सेमल लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया है। यह कार्रवाई तालझारी प्रखंड अंतर्गत कैरासोल-बांझी रोड स्थित कचहरी मौजा के निकट की गई। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की जा रही है एवं पूछताछ किया जा रहा है ।वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रभारी रेंजर श्री पंचम दुबे, वनपाल राणा रंजीत, तथा वनरक्षी पप्पू कुमार यादव, प्रेम कुमार, राजेश टुडू सहित अन्य वनकर्मी उपस्थित थे।यह आशंका जताई जा रही है कि लकड़ी की अवैध कटाई कर उसे बाहर भेजने की तैयारी थी। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और वन विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहा है।वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन संपदाओं की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

भीषण गर्मी को देखते हुए मिजाचीकी स्टेशन परिसर पर ठंडा पानी की व्यवस्था की गई

मंडरोःमिर्जाचौकी स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक के केबिन के पास तपती धूप और गर्मी में रेल यात्रियों के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था की गई। धूप की तपिश बढ़ाने के साथी जरूरतमंद यात्रियों के लिए शीतल जल की सुविधा के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था की गई। मालदा रेल मंडल के डीआरएम के निर्देश पर इस तरह की व्यवस्था रेलवे स्टेशन प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराई गई। साथ ही व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन के लिए बीच-बीच में निरीक्षण करने की बात कही गई । वही मिजाचौकी रेलवे स्टेशन प्रबंधक अनिल वर्मा ने कहा कि धूप की तेज तपिश बढ़ने के कारण लोग पानी पीने को यहां वहां भटक रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मिजाचौकी रेलवे स्टेशन परिसर पर ठंडा पानी का व्यवस्था किया गया है ताकि भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

समर कैंप में हुए प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने लिया हिस्सा

रिपोर्ट अविनाश मंडल

पाकुड़ःपाकुड़ प्रोजेक्ट परख के तहत जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय, डिस्ट्रिक सीएम एसओई पाकुड़ राज, सीएम एसओई गर्ल्स पाकुड़, रानी ज्योतिर्मय गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़, सीआरसी धनुषपूजा, मॉडल स्कूल काशीला, आरके 10+2 हाई स्कूल बिरकिट्टी महेशपुर, 10+2 हाई स्कूल महेशपुर सहित अन्य विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में छात्राएं योग, मेहंदी, पेपर क्राफ्ट और ड्राइंग, खेलकूद, संगीत प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पुरती ने कहा कि बेटियों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह के आयोजन से छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती हैं। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और संगीत में भी आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि यह कैंप जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। इससे छात्राओं में आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

शनि महाराज का वार्षिक पूजनोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर। बैधनाथधाम रेलवे स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में श्री श्री 108 शनि महाराज का वार्षिक पूजनोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शनि महाराज का तेल से अभिषेक किया गया। बड़े ही विधि-विधान से मंदिर के पुजारी द्वारा विधिवत पूजा की गई। शनि महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया। महाआरती की गई। खिचड़ी का भोग लगाया गया। भक्तों एवं आगन्तुकों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। पूरें मंदिर एवं इर्द-गिर्द क्षेत्रों को रंग-बिरगें आकर्षक लाईटों से सजाया गया। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी गई। मौके पर हिन्दू विकास मंच (समत्र-भारत) के जिला अध्यक्ष प्रभाष गुप्ता ने लोगो के ग्रह-संकट से मुक्ति एवं सुख-शान्ति की कामना श्री शनि भगवान से की।

टीचर्स ऑगेर्नाइजेशन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक सह अधिवेशन संपन्न

कार्यालय @ डॉ सुनील खवाड़े, मुख्य संरक्षक, आल इंडिया फेडरेशन आफ टीचर्स आर्गनाइजेशन

आल इंडिया फेडरेशन आफ टीचर्स आर्गनाइजेशन का अधिवेशन संपन्न

शिक्षकों के हमदर्द बनें डॉ सुनील, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहने का दिया वचन

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

मुख्य बिंदु--डॉ सुनील खवाड़े को विधिवत रूप से बनाया गया मुख्य संरक्षक --एक देश एक पाठ्यक्रम, समान वेतन, समान सेवानिवृत्त उम्र की मांग--ध्वनिमत से पारित किया गया प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगी गुहार--आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सितंबर में होगा अगला अधिवेशन --22 राज्यों से 25 संगठन और 68 शिक्षक हुए शामिल डाबरग्राम स्थित पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को आल इंडिया फेडरेशन आफ टीचर्स आर्गनाइजेशन की अधिवेशन आयोजित की गई। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अश्विनी कुमार ने किया। अधिवेशन की शुरूआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान *डॉ सुनील खवाड़े को विधिवत रूप से एआईएफटो का मुख्य संरक्षक* के पद पर मनोनीत किया गया। मनोनयन उपरांत सभा ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पर सहमति देते हुए तालियां बजाकर मुख्य संरक्षक का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्हें सम्मान स्वरूप साफा पहनाकर दायित्व सौंपा। डॉ सुनील ने सबों का अभिवादन स्वीकार किया और हर परिस्थिति में शिक्षकों के साथ रहने का वचन दिया। विभिन्न सत्रों में आयोजित अधिवेशन में डाल्फिन डांस अकदामी के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। अधिवेशन में शिक्षा व शिक्षकों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पेश किया गया जिसे शिक्षकों ने ध्वनिमत से समर्थन किया। पारित किये गये प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपने का निर्णय लिया गया ताकि समस्याओं के समाधान में अग्रेतर कारवाई की जाए।

शिक्षकों ने उठाई देशभर में समानता की मांग

अधिवेशन के दौरान शिक्षकों ने समानता की मांग उठाई। संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की समान उम्र, शिक्षकों के समान वेतनमान की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि हर जगह अलग अलग पैमाने के वजह से एक समान काम नहीं हो पा रहा है जिससे अपेक्षित विकास और सुधार नहीं हो पा रहा है। अधिवेशन के दौरान प्राइवेट स्कूल की संख्या में एकाएक हो रही बेतहाशा वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त किया गया।

यूजीसी की तर्ज पर एसजीसी के गठन की मांग

शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर स्कूलों के लिए विद्यालय अनुदान आयोग के गठन पर जोर दिया। अधिवेशन में

कहा गया कि विश्वविद्यालयों के लिए एक आयोग है जिसपर हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है, अनुदान मिलता है। वैसे ही विद्यालयों के लिए भी समान आयोग का गठन किया जाए ताकि शिक्षा और शैक्षणिक स्तर के समग्र विकास पर काम किया जा सकें। वक्ताओं ने कहा कि जब तक एक समान पाठ्यक्रम नहीं होगा सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के रुझान में वृद्धि होगी। साथ ही देश की कुल जीडीपी का न्यूनतम छह प्रतिशत राशि शिक्षा में खर्च करने की मांग की गई।

ये थे मंचासीन - - - - - - - -

गुजरात से रमेश भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, हितेश भाई पटेल, केरला से एम. सलाहुद्दीन, तेलंगाना से एमएलसी श्रीपल रेड्डी पिंगली, हिमाचल प्रदेश से अवनित सरक्रिक, उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार सिंह, राजस्थान से छगनलाल रोज, तेलांगना से पद्मा गोली, राजस्थान से हरि सिंह मिथरवाल, हिमाचल प्रदेश से प्रेम लाल शर्मा।

मजबूत शिक्षक, मजबूत भविष्य की नींव हैं : डॉ सुनील खवाड़े

आज बड़ा ही खुशी का दिन है। जेएसपीटीए के लिए भी यह बहुत बड़ा दिन है। ऐसे आयोजनों से शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमलोग अपने उद्देश्य में निश्चित रुप से सफल होंगे। आज की उपस्थिति कोई साधारण उपस्थिति नहीं है, यह हमारे लिए गौरव का दिन है। आयोजन के प्रति शिक्षकों का रुझान अभूतपूर्व है।ऐसे आयोजन हर वर्ष होना चाहिए,संगठन को समय और इच्छा जाहिर करना है, मैं हर तरह से शिक्षकों के साथ हूं। न केवल जिला बल्कि प्रखंड स्तर पर भी आयोजन किया जाए।सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। देवघर नटराज की नगरी ज्योतिर्लिंग व ह्दयापीठ है, बहुत जल्द मैं फिर से आपलोगों को बुलाउंगा।

झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का पुनर्गठन

डॉ सुनील खवाड़े मुख्य संरक्षक, अशोक कुमार मिश्र अध्यक्ष निर्वाचित झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव रविवार को चुनाव पर्यवेक्षक राजेश कुमार मिश्र के देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान चुनाव पदाधिकारी मदन कुमार रत्न भी मौजूद थे। चुनाव सर्वसम्मति व निर्विरोध तरीके से संपन्न किया गया। इस दौरान डॉ सुनील खवाड़े को मुख्य संरक्षक के तौर पर घोषित किया गया। साथ ही अशोक कुमार मिश्रा को अध्यक्ष घोषित किया गया। डॉ सुनील खवाड़े ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि मैं शिक्षकों के प्रति शुक्रगुजार हूं। मैं जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं और शिक्षकों के हित में हर तरह से हर परिस्थिति में शिक्षकों के साथ हूं और उनकी हर तरह की समस्याओं के निराकरण के समाधान का आश्वासन देता हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षक मजबूत भविष्य की नींव हैं।

नवमनोनीत कमेटी का प्रारूप--------

डॉ सुनील खवाड़े - मुख्य संरक्षक ॉ राजेश कुमार मिश्र - संयोजक अशोक कुमार मिश्र - अध्यक्ष जयंती देवी, पूनम कुमारी, शिवनाथ भगत - उपाध्यक्षमंगलेश्वर उरांव - महासच्चिुभाष कुमार - कोषाध्यक्ष मदन कुमार रत्न - संयुक्त सचिव नीरज कुमार, जीवननाथ तिवारी, उषा ब्रेक, उपेंद्र प्रसाद, राजकमल दूबे - उप महासचिव मुकेश कुमार, देवकांत मंडल, जेराम चेरमाको, अवधेश कुमार - संगठन सचिव देवन्ती कुजूर - अंकेक्षक जसिंता कुजूर - महिला नेटवर्क अनिल कुमार - प्रवक्ता

डीसी व एसपी ने मॉडल आंगनवाड़ी , अबुआ आवास एवं प्रकृति विहार पार्क का किया निरीक्षण

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़ःपाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड के डाकबंगला स्थित पार्क पहुंचे वहां देखभाल रखरखाव सहित अन्य कार्यों की जानकारी ली और पार्क को डेवलप करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश बीजीआर कोल कंपनी के अधिकारी को दिया। डीसी व एसपी ने अबुआ आवास का किया निरीक्षण इसके अलावा उपायुक्त मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड के सालपतरा में अबुआ आवास का निरीक्षण किया

गया।उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे घरों का जायजा लिया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। उन्होंने निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने हेतु लाभुकों को निर्देशित किया और कहा कि 28 मई को सभी लाभुकों का एक साथ गृह प्रवेश कराया जाएगा। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने बनाए जा रहे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण उपायुक्त मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड के सालपतरा में बनाए जा रहे मांडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर, आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 10 मांडल आंगनबाड़ी केंद्र बनायें जा रहे हैं।

पाकुड़ जिले के लिए 3150 क्विंटल धान का बीज हुआ प्राप्त, किसानों के बीच किया गया वितरण

रिपोर्ट अविनाश मंडल

पाकुड़ःपाकुड़ रविवार को संयुक्त कृषि भवन, पाकुड़ में बीज दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जन प्रतिनिधिगण, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक,तकनीकी सहायक एवं अन्य उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में किसानों को खरीफ मौसम में खरीफ के मुख्य फसलों जैसे धान, मक्का, ज्वार, रागी, तिल, उरद, अरहर आदि के प्रभेदों से अवगत कराया गया एवं बीज विनिमय वितरण तथा बीजोत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ फसलों हेतु विभिन्न लैंप्स एवं एफपीओ में बीज की उपलब्धता की जानकारी किसानों को दी गई। जिला पाकुड़ हेतु कुल 3150 क्विंटल धान बीज एवं अन्य बीज का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे किसानों के बीच 50 प्रतिशत अनुदान पर जिला अंतर्गत लैंप्स एवं एफपीओ के माध्यम से ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी अंतर्गत ओटीपी के द्वारा वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को अन्य योजनाओं जैसे बिरसा फसल विस्तार योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अंतर्गत क्लस्टर में शत प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले बीजों की जानकारी दी गई। अंत में खरीफ मौसम हेतु बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपस्थित किसानों के बीच धान बीज का वितरण जन प्रतिनिधि, जिला कृषि पदाधिकारी एवं भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा किया गया.

आजिविका स्वंय सहायता समूह के मदद से तकनीकी खेती कर आत्मनिर्भर बन रही माया दीदी

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़ःपाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखण्ड स्थित बलियापत्रा गांव की माया देवी ने गणेश आजीविका सखी मंडल से जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रही है। माया दीदी ने बताई की 2017 से पहले पारंपरिक खेतीबाड़ी करती थी और दोनों पति-पत्नी मजदूरी कर अपना भरण पोषण किसी तरह कर पा रही थी। 2017 में देखी कि गांव में कुछ दीदी के द्वारा जेएसएलपीएस समूह का गठन किया जा रहा है तब माया दीदी भी गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह में जुड़ने के पश्चात समूह से 16 हजार रुपये ऋण ली और अपने जमीन पर बैंगन और टमाटर की खेती की जिससे 65 हजार का मुनाफा हुआ। 2021 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अंतर्गत संचालित जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) परियोजना से जुड़कर सूक्ष्म टपक सिंचाई यंत्र प्राप्त हुआ तब माया दीदी

16 हजार रुपये ऋण वापस कर फिर गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह से 1 लाख की ऋण लेकर ड्रिप बोरिंग की। साथ ही खफ्एऊअ से कुसुम योजना का लाभ भी प्राप्त की और 33 डिसमिल जमीन में सूक्ष्म टपक सिंचाई के माध्यम से रेड लेडी प्रजाति की पपीता और 25 डिसमिल में फूलगोभी की खेती नामधारी किस्म का करके 2 लाख 50 हजार की शुद्ध आमदनी कर 1 लाख ऋण वापस किया। माया दीदी को इस वर्ष उद्यान विभाग से उद्यान विकास योजना अंतर्गत मल्चिंग प्लास्टिक का लाभ भी मिला है। अब इस वर्ष अप्रैल 2024 में पुनः माया दीदी ने रेड लेडी किस्म का पपीता की खेती के लिए मुनिवर नर्सरी गुजरात से कुल 300 पौधा ऑनलाइन के माध्यम से क्षेत्र विषयक समन्वयक के सहयोग से मंगवा के लगाई उसमें से 140 पौधा से ही अभी तक कुल 2000 किलो पपीता 65 रु प्रति किलो के दर से लोकल मार्केट में बेच कर 1 लाख 30 हजार रुपये आमदनी कर चुकी है जिसमे अभी तक 70 हजार रुपए कुल खर्च हो चूका है और शुद्ध आमदनी 60 हजार रुऊ हुआ है। अभी भी 30 हजार रुपए आमदनी होने का अनुमान है। अप्रैल 2025 में भी माया दीदी अन्य 25 डेसीमल प्लाट में श्ठफअमीना किस्म का पपीता का कुल 250 पौधा लगा चुकी है। माया दीदी समूह में जुड़ने के बाद तकनीकी खेती कर अच्छी आमदनी कर रही है। साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की योजना बना रही है। अपने संवरते जीवन से दीदी काफी खुश है दूसरे दीदियों को इस नए तकनीकी से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है।

गंधरिया पंचायत में ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्न पर जागरूकता शिविर का आयोजन

दिव्य दिनकर संवाददाता चतरा

गंधरिया पंचायत में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के तत्वावधान में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' विषय पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति ग्रामीण समाज में जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर विधिक सेवक जुलकर नैन एवं रेणु कुमारी उपस्थित थे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बालिकाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने,उन्हें शिक्षा के समान अवसर देने तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी दी। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की उपस्थिति रही। सभी ने इस पहल की सराहना की और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प लिया।

उपायुक्त ने जिले में 16 वें वित्त आयोग की आयोजित बैठक को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर की अध्यक्षता में आज दिनांक 25.05.2025 को गोपनीय सभागार में 16 वें वित्त आयोग की आयोजित बैठक हेतु की जाने वाली तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 29 मई को 16 वें वित्त आयोग की टीम आयोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगढ़िा के नेतृत्व देवघर आ रही हैं। ऐसे में बैठक को लेकर की जाने वाली विभिन्न तैयारियों की बिंदुबार समीक्षा करने के अलावा विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को

लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त विशाल सागर ने केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में 16वें वित्त आयोग के एजेंडा से सभी को अवगत कराया। साथ ही वित्त आयोग की केंद्रीय टीम प्रमंडल स्तर पर बैठक करेगी व सहायता अनुदान पर पंचायतों व निकायों से राय लेगी। साथ ही वित्त आयोग की टीम देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा व पाकुड़ जिले के जिला परिषद अध्यक्ष, एक मुखिया व एक प्रमुख के साथ बैठक को लेकर की जाने वाली तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। *इस दौरान उपरोक्त के अलावा* अपर समाहर्ता हीरा कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला योजना पदाधिकारी मुकेश कुमार, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं नजारत व परिवहन विभाग की टीम उपस्थित थी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगामी 27 तारीख को महाधरना

जाति आधारित जनगणना का करेगी विरोध

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर-झारखण्ड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आगामी 27 मई को पार्टी देवघर जिला समाहरणालय के समक्ष केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम करनें जा रहा है।इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों की अच्छी जुटान होगी।वहीं आगे दशार्या है कि हाल के दिनों में भाजपा नीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जाती आधारित जनगणना करवाने का निर्णय लिया है पार्टी इस महाधरना के माध्यम से मांग करेगा कि जाति आधारित जनगणना में सरना धर्म कोड/आदिवासी धर्म कोड को लागू किया जाए।बिना सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लागू किये जाती आधारित जनगणना का झारखण्ड मुक्ति मोर्चा विरोध करता है और जब तक उक्त दोनों धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है,तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जाती आधारित जनगणना झारखण्ड में नहीं होने देगा।सरना धर्म कोड/आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के लिए जेएमएम चरणबद्ध आंदोलन करेगा और और जब तक इसे लागू नहीं किया जाता है आंदोलन जारी रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

बकरीद को लेकर नगर थाना में शांति समिति की हुई बैठक

कानून हाथ में लिया तो नहीं मिलेगी राहत- एसडीपीओ

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़ः बकरीद पर्व को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आजाद ने की, वहीं बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू समेत थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।एसडीपीओ दयानंद आजाद ने कहा कि उपायुक्त पाकुड़ के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है ताकि बकरीद के मौके पर किसी भी प्रकार की अफवाह या शांति भंग करने वाली घटनाओं पर पहले से ही कड़ी नजर रखी जा सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभी समुदाय एकजुट होकर मनाएं त्योहार- बीडीओ

बैठक में बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने कहा कि पाकुड़ की गंगा-जमुनी तहजीब हमेशा मिसाल रही है। बकरीद जैसे पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रशासन को सहयोग करें और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत सूचना दें।

प्रशासन ने दिए निर्देश, पर्व पर दिखेगा चौकसी का माहौल

बैठक में मौजूद लोगों से सुझाव भी लिए गए। तय हुआ कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी और ड्रोन से भी निगरानी की जा सकती है। अफसरों ने साफ किया कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

वट सावित्री पूजा को ले खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर. शहर के बाजारों मे वट सावित्री पूजा को लेकर रविवार को बाजारों में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। वट सावित्री पर्व सोमवार को आयोजित होगी। इसे लेकर बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने बास के पंखा,बांस के डाला और फल ,फूल,श्रृंगार की सामने की खूब खरीदारी की। विवाहिता के लिए वट सावित्री व्रत हाथ से बने बास के पंखे और बस की डाली का विशेष इस पूजा का विशेष महत्व है। हिदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित महिला इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से रखती है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पति पर आई सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है,साथ ही भविष्य भी बेहतर होता हैं।

समाजसेविका सावित्री देवी के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन

दिव्य दिनकर संवाददाता

रांची- विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़ी समाजसेविका सावित्री देवी का निधन 18.5.2025 को हो गई। न्यू मधुकम,गोपाल मंदिर रोड निवासी(71 वर्षीय) स्व.सावित्री देवी श्री मुनिलाल मिस्त्री की धर्मपत्नी थीं जो अपने पीछे दो पुत्र बलराम शर्मा,रवि राणा एवं तीन पुत्री सुनैना देवी,गायत्री शर्मा,खुशबू शर्मा सहित भरा पूरा छोड़ गई।समाजसेविका सावित्री देवी के निधन पर विश्वकर्मा युवा सुरक्षा मंच काफी दुखित है।आज दो मिनट मौन धारणकर उन्हें याद कर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया।मंच के राष्ट्रीय मुख्य संयोजक संतोष कुमार श्रेयांश ने कहा वे समाज के हर सुख दुख मे साथ रहती थी,उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन,पूजा पाठ एवं धार्मिक आयोजन मे व्यतीत होता था।आज उनकी कमी हम सभी लोगों को महसूस हो रही है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा ने कहा फ्री मेडिकल कॉलेज,पौधारोपण, जरूरतमंदों के बीच पौष्टिक भोजन,भजन कीर्तन आदि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजन कर स्व.सावित्री देवी को हमेशा याद किया जाएगा। आज शोक सभा में मुख्यरूप से सरयू शर्मा,राहुल चौधरी,दीपक बर्मन,डॉक्टर दुर्गा लाल शर्मा,डॉक्टर एल.के.शर्मा,अजय शर्मा,रामलखन साहू,कृष्णा शर्मा,सुदर्शन शर्मा,जितेंद्र शर्मा,राजेन्द्र प्रसाद,सुभाष कुमार,बजरंज शर्मा,प्रिंस राज,रुद्र प्रताप,दिव्यांशु कुमार,वीर प्रताप,यश राज,प्रियांशु कुमार आदि मौजूद थे।यह जानकारी क्लब के पी.आर.ओ.सुभाष कुमार ने दी है।

सड़क हादसे मे घायल युवती की इलाज के दौरान मौत

दिव्य दिनकर संवाददाता

मांडर - थाना क्षेत्र में छह दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल कांके के अरसंडे निवासी अन्नपूनी कुमारी 23 वर्ष की शनिवार को मांडर के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गयी. पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. जानकारी के अनुसार अन्नपूनी कुमारी पिता विजयनाथ साहू 18 मई को मांडर के करगे गांव स्थित अपनी चचेरी बहन के घर मेहमान आयी थी. और वहीं से 19 मई को अपने भतीजे के साथ बाइक में बुढ़मू के तिरुफॉल घूमने जा रही थी. इसी क्रम में हातमा मोड़ के निकट सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया था. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल अनुपुर्णी कुमारी को इलाज के लिए मांडर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां शनिवार की सुबह करीब सात बजे उसने दम तोड़ दिया!

निराश्रित बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु 'साथी' टीम का गठन 26 मई से शुरू

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़ःझालसा रांची के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद की अध्यक्षता में सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में आधार के लिए सर्वेक्षण और ट्रैकिंग और समग्र समावेशन तक पहुँचर के लिए साथी समिति का गठन किया गया है। जिसमें उपस्थित सभी सहभागी को प्रशिक्षित किया गया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद ने गठित साथी समिति के सदस्यों को कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए असहाय बच्चों के साथ अधिकारी बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बन कर कार्य करते हुए अपने भूमिका को निभाने को कहा गया। साथी समिति के गठन टीम को कर्तव्यनिष्ठ हो कर अपने दायित्व को निभाने को कहा गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ को सूचित करने को कहा गया। निराश्रित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु कई पहलुओं पर चर्चा की गई। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बैठक का मुख्य उद्देश्य साथी अभियान के तहत वंचित बच्चों को कानूनी पहचान दिलाना व उन्हें सामाज कल्याण की योजनाओं से जोड़ना था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) के तहत न्याय व समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में कई ऐसे असहाय बच्चे हैं,

जो सड़कों या देखभाल संस्थानों में जीवनयापन कर रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है। यह पहचान पत्र उन्हें सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल संरक्षण कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। साथी अभियान इन बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, आधार पंजीकरण व कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अहम भूमिका है। बैठक में इस अभियान को मिशन मोड में लागू करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अभियान को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागीय सहयोग और योगदान की प्रतिबद्धता जताई। डीएलएसए द्वारा इस अभियान को मिशन मोड में संचालित किया,जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण, आधार पंजीकरण व कानूनी सहायता की प्रक्रिया शामिल होगी। अभियान 26 मई से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में आधार पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बाल कानूनों पर भी गंभीर और विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस पहल को बच्चों के उज्वल भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया।इस कार्यक्रम के तहत साथी समिति गठन के सदस्यगण को इस अभियान में उनकी अहम भूमिका और जिम्मेवारी को सफल पूर्वक निभाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दी गई। मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) व्यास ठाकुर,पाकुड़ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़,सिविल सर्जन मंटु कुमार टेकरीवाल पाकुड़ जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी, पाकुड़, विनोद कुमार, एसआई, पाकुड़ (टी) पी.एस,बाल आश्रय गृह के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह,एंथनी मरांडी, रवि कुमार, टेफॉन सोरेन,पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा, कौशिक कुमार,पीएलवी उत्पल मंडल, विजय कुमार राजवंशी, चंद्र शेखर घोष,एवं नीरज कुमार राउत ने भाग लिया। इस दौरान संबंधित विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रखंड अंजुमन इस्लामिया मांडर के सदर नुरुल्लाह हबीब नदवी ने अपनी टीम के साथ जयहिंद सभा स्थल का किया निरीक्षण

दिव्य दिनकर संवाददाता

मांडर - मांडर प्रखंड अंजुमन इस्लामिया मांडर के सदर नुरुल्लाह हबीब नदवी ने रविवार को इटकी के कुंदी मैदान में 27 मई को आयोजित हो रहे जयहिंद सभा स्थल का निरीक्षण अपनी टीम के साथ किया,ज्ञात हो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है,

सांसद इमरान प्रतापगढ़ी होंगे मुख्य अतिथि

कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता केन्द्रीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य सभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि होंगे इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री के राजू जी, पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, सहित झारखण्ड

कांग्रेस के सभी वरीय नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. जानकारी के मुताबिक पुरे रांची जिला और झारखंड के 30 हजार से अधिक लोगों की इस सभा में उपस्थित होने की सम्भावना है । मौके पर नुरुल्लाह हबीब नदवी के अलावा प्रोफेसर मजहर इमाम, तावेज खान, परवेज अंसारी, अमानुल्लाह अंसारी, नेशार अख्तर, तौकिर कामरान, साद अंसारी, ताहिर अंसारी, टीपू, रुस्तम अंसारी, सिकंदर अंसारी, तनवीर अंसारी,सहित अन्य लोग उपस्थित थे ।

शहीद जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़ःअमडापाड़ा प्रखंड के अंबा जोड़ा ग्राम में अमर शहीद जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी की स्थापना की गई और आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित किया गया और अनावरण समारोह को धूम धाम के साथ मनाया गया। आसपास से आए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिवचरण मालतो ने तिलका माझी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा 1750 ईड्ड में सिंगारसी पहाडी क्षेत्र के गड़गामा में जन्मे तिलका माझी गुरिल्ला युद्ध के महानायक बिदेशी आक्रमणकारी को मार भगाया और जमीन को बचाने के लिए अपने आप को अंग्रेजो के हांथों से फांसी को स्वीकार किया, और जमीन बचाई उसी की देन है कि हम आज खुले आसमान के नीचे सुख - शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। उनका प्रेरणा ले कर हमें आगे बढ़ना होगा। हर शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आना होगा ।साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में,कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना होगा। तभी हम जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। साथ ही प्रत्येक गाँव में अमर शहीद जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी की प्रतिमा का स्थापना करना अति आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में लेखक बृंद आज के दिन में तिलका माझी

को छुपाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा इसीलिए एकजुटता के साथ चलना होगा। ग्रामीणों ने अतिथियों को माला पहना कर और प्राकृतिक टोपी पहना कर स्वागत किया । मौके पर समाज सेवी बैजनाथ पहाड़िया मुख्य सलाहकार, डेविड मालतो, मरकस मालतो, बैजनाथ पहाड़िया केंद्रीय उपाध्यक्ष, रामि पहाड़िन मुखिया,कमलेश्वर पहाड़िया प्रवक्ता, धर्मेंद्र पहाड़िया मुखिया आदि ने सभा को संबोधित किया ।

कुटुंबा प्रखंड में 19.03 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 31 प्री-फैब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- बिहार सरकार के मंत्री मंगल पाण्डेय स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, बिहार सरकार द्वारा औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड में 19.03 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 31 प्री-फैब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया। बिहार सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर, सुलभ एवं सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयासरत है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार द्वारा औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व में मॉडल अस्पताल, औरंगाबाद का उद्घाटन प्रगति यात्रा के दौरान किया गया था। वर्तमान में 21 करोड़ रुपये की लागत से मातृ शिशु अस्पताल, औरंगाबाद का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सदर अस्पताल परिसर में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से प्री-फैब पीआईसीयू अस्पताल तथा 7.5 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड प्री-फैब फील्ड अस्पताल, जम्हौर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हाल ही में जिले में 34 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर आम जनता को समर्पित किया गया है। औरंगाबाद जिले में 9.64 करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 400.29 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपये की लागत से जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थान का निर्माण कार्य भी सदर अस्पताल परिसर में कराया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु जिले के छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20 शैय्या युक्त प्री-फैब वार्ड तथा मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (टऋढ्ढर) की अधिष्ठापना की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में यह सतत प्रगति राज्य सरकार की दूरदर्शता, जनकल्याण की प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक तत्परता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।

प्लाई ऐश ढुलाई की पेटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मची होड़, एनटीपीसी अधिकारियों पर बन रहा दबाव

छह ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों को मिला ठेका, हाईवा एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

दिव्य दिनकर संवाददाता टंडवा, चतराः-

एनटीपीसी टंडवा में कोयले की राख (प्लाई ऐश) की ढुलाई को लेकर पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेने की होड़ तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी आगामी 12 महीनों में ऐश पोंड से राख ढुलाई पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस कार्य के लिए 27 फीसदी कम दर पर छह ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों को ठेका दिया गया है। जैसे ही इन कंपनियों के नाम सामने आए, पेटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजनीतिक हस्तियों से लेकर अधिकारियों तक की सिफारिशें शुरू हो गईं। एनटीपीसी कर्णपुरा के अधिकारियों पर स्थानीय से लेकर राजधानी रांची और दिल्ली तक से दबाव डाला जा रहा है ताकि चहेते लोगों को काम दिलाया जा सके। इस बीच हाईवा एसोसिएशन ने एनटीपीसी प्रबंधन को पत्र भेज कर विरोध जताया है। उनका कहना है कि निर्धारित दरें इतनी कम हैं कि ईमानदारी से काम कर पाना संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि इन छह कंपनियों में से कौन ह्वबैग टू बैगह्ल कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल होती है। लेकिन एक बात तय है–आगामी दिनों में क्षेत्र की सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ना तय है।

झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की बैठक संपन्न

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

आज दिनांक 25/05/2025को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ झारखंड जिला कमिटी देवघर की बैठक रूबी कुमारी जिला अध्यक्ष देवघर की अध्यक्षता में संपन्न हुई । आज की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर केंद्र और राज्य सरकार के प्रति रोष प्रगट किया गया । बैठक में उपस्थित सेविका सहायिका ने एक स्वर में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की आपसी लड़ाई में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का केंद्रांश राशि विगत 5 वर्षों से कभी भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और न ही वर्षों मानदेय में वृद्धि की जा रही है। राज्य सरकार ने तो कुछ मानदेय बढ़ाए मगर केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाया जो चिंता का विषय है । झारखंड में महिला सम्मान के नाम चल रही मईया योजना राज्य की पूरी अर्थ व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है । विभागों में काम करने वाले कर्मियों का मानदेय लंबे समय से बकाया है ।यदि महिला सम्मान का पैमाना ढाई हजार ही है तो राज्य के इस नीति को बनाने वाले माननीय मंत्री विधायक और नौकर शाह अपनी लक्जरी बंगले गाड़ी ,वेतन भत्ता सुविधा को त्याग कर राज कोष में दान कर दे और हर महीने ढाई हजार राशि वेतन के रूप में ले ।राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए घातक मईया योजना को ऐसे प्रचार किया जा रहा है मानो यह भारत रत्न , पद्म श्री पद्म भूषण और राष्ट्रपति पुरस्कार है ।

सरकार ने पहले कर्मचारी आंदोलन को कमजोर करने लिए स्थायी कर्मियों के विरोध में अनुबंध/संविदा और दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारियों की भर्ती की नीति लाई ,जब अनुबंध कर्मी हक मांगने के लिए आंदोलन और कोर्ट जाने लगे तो इस आंदोलन को फिर कमजोर करने लिए आउट सोर्सिंग कंपनियो के माध्यम से देय मानदेय का एक वर्ष की सैलरी या 10 गुणा पगड़ी लेकर बहाली कर अनुबंध कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर करने की चाल चली गई , आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विकल्प के रूप में

अपनी राजनैतिक रोटी सरकारी खजाने को लुटाकर सेंकने के लिए मईया योजना लाया है । हम सबों को सरकार की इस दुष्ट नीति को समझना होगा और राज्य को बर्बाद करने पर तुली इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा । शिक्षा जगत के लिए अभिशाप बनी झारखन्ड सरकार ने स्कूल पूर्व शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी और स्कूली शिक्षा के केंद्र सरकारी विद्यालयों को निजीकरण करने और दलित, आदिवासी हरिजन, अल्प संख्यकों और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए झारखंड सरकार ने शिक्षक का प्राथमिक ,मध्य और माध्यमिक आचार्य का नामकरण करण कर वर्षो से निर्धारित सम्मान जनक ग्रेड पे 4200,4600,और 4800, को विलोपित कर चाइना कट ग्रेड पे 2400 और 2800 देकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिभा को अपमानित कर दिया है । शिक्षक नियुक्ति की प्रकिया में परीक्षा के चरण बढ़ते गए और ग्रेड पे बढ़ती महंगाई में घटा कर अपनी नीच सोच का परिचय दिया है कि राज्य की सत्ता अयोग्य लोगों के हाथों में है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लोहे के गेट के समान बनाकर इसे अभेद्य किया गया है ।उसे नियुक्ति नहीं करनी है मामला कोर्ट में फंसा कर जनता में घड़ियाली आंसू बहाकर सहानुभति लेना है । दलित आदिवासी हरिजन और अल्पसंख्यक के प्रति झूठी प्रेम दिखा कर पूरी अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करना इस सरकार की मंशा है। जिस सरकार के पास महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंत्री नहीं वह सरकार महिला सम्मान की बात पर बैनर पोस्टर में होर्डिंग लगा कर बड़ी बात करे तो यह भद्दा मजाक है । वर्तमान सरकार के शासन काल में चरम पर पहुंची भ्रष्टाचार के कारण आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तबाह है ।जिलो मानदेय रोक दे बर्खास्त कर दे ,वार्षिक मानदेय वृद्धि नहीं दे ,इसकी शिकायत और निवारण का रास्ता बताने वाला कोई भी है । आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में नित दिन नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर परेशान करना आम बात हो गई है । आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के नाम बिना काम के स्मार्ट फोन दिया गया ,इसके रिचार्ज की व्यवस्था नहीं की गई ।दर्जनों काम सौंप कर महीनों मानदेय बकाया रखना , झारखंड सरकार की महिला सम्मान की यही नीति है । मानदेय ,पोषाहार ,मकान किराया भुगतान में ही अव्यवस्था नहीं है बल्कि केंद्र के लिए मिलने वाला पोषाहार का बाजार दर से काफी अंतर है ।। सरकार अपनी नीति में बदलाव नहीं किया और झूठी महिला सम्मान के नाम पर राज्य में अपना प्रचार किया तो आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़क पर उतर कर सरकार की फर्जी महिला सम्मान की नीति का पदार्फाश करेगी इसकी तैयारी राज्य कमिटी की बैठक में जल्द लिया जाएगा । आज की बैठक में रूबी कुमारी,प्रमिला यादव, सुधा देवी,शान्ति कुमारी राखी देवी,विद्या देवी, सहित सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया।

सेना में दिखने लगा महिला शक्ति का दम

>> विचार

"रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी।

रमेश सर्राफ धमोरा

भारतीय सेना में महिला शक्ति का दम दिखाई देने लगा है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सेना में बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में सेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा युद्ध से संबंधित जानकारी देना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के पराक्रम की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कैसे और क्या कार्यवाही की। सेना की दोनों महिला अधिकारियों ने सैनिक कार्यवाही की हर दिन प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से देश दुनिया को ताजा जानकारी प्रदान कर यह दिखा दिया कि भारत में महिला शक्ति भी किसी से कम नहीं है।भारत में सदियों से महिलाओं को मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता रहा है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया: ।। अर्थातः जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। जहां नारियों की पूजा नहीं होती, वहां किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। हम देश में साल में दो बार नवरात्र पर मातृशक्ति रूपी मा दुर्गा की पूजा कर देश दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं है। अब तो हमारी सेना में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपनी उत्कृष्ट क्षमता दिखा दी है। महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तो युद्ध भूमि में हर प्रकार की भूमिका निभाने को तैयार नजर आ रही है।भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास लंबे संघर्ष और बदलावों से भरा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही महिलाएं भारत की सुरक्षा और सेवा में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। लेकिन सेना में औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति का रास्ता बहुत बाद में खुला। साल 1943 में बनी रानी झांसी रेजिमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। यह पहली बार था जब महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर सक्रिय रूप से दिखाई दी। आजादी के बाद भी सशस्त्र बलों में महिलाओं को लंबे समय तक सहायक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया।भारत की तीनों सेनाओ (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) में महिलाओं की संख्या को लेकर अगस्त 2023 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि तीनों सेना में 11414 महिलाएं सेवाएं दे रही है। थल सेवा में 7054 महिलाएं सेवारत है। इनमें 1733 महिला अधिकारी है। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। भारतीय वायु सेवा में 1654 अधिकारी सेवारत है

जबकि 155 महिलाएं एयर मेन (अग्निवीर) के रूप में सेवा दे रही है। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत है जबकि 727 महिलाएं सैलर्स (अग्निवीर) के तौर पर तैनात है।इसी तरह 1212 महिलाएं भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में 168 महिलाएं आर्मी डेंटल कार्स में और 3841 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कार्यरत है। 151 महिलाएं नौसेना के मेडिकल कॉर्प्स में 10 महिलाएं डेंटल कार्य और 380 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत है। 274 महिलाएं भारतीय वायु सेवा के मेडिकल कॉर्प्स में पांच महिलाएं डेंटल कॉर्प्स में और 425 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत है।पहले महिलाओं को शार्ट सर्विस कमीशन में ही लिया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन मिलने लगा है। अब एनडीए की कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटों पर लड़कियां सिलेक्ट होती है और वह भी ओपन कंपटीशन में मुकाबला करके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2022 में महिला कैडेट्स के पहले बैच की एंट्री के बाद से अब तक एनडीए में 126 महिलाओं को एडमिशन मिला है। आर्म्ड फोर्सज में आने के बाद उनके लिए भी अवसर समान होते हैं। उनका करियर प्रोग्रेस वैसा ही होगा जैसा लड़कों का होगा। सर्विस रूट समान होते हैं। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सेना में पूरी तरह जेंडर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है।सेना में आज हमारी महिला कॉम्बैट पायलट भी है। जो मिसाइल चलती है मोर्चे पर भी जाती है। वह इंजीनियरिंग का कार्य भी देखती है और सैटेलाइट को भी नियंत्रित करती है। अब महिलाएं डिफेंस भी करती है। टेक्निकल इंटेलिजेंस भी एकत्रित करती है। अभी तक आमने-सामने की लड़ाई में महिलाओं को नहीं भेजा जाता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह 2016 में भारतीय वायु सेवा की तेजस फाइटर स्पाइडर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले वह मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन भी उड़ा चुकी है। ग्रुप कैप्टन सालिया धामी वायु सेवा की ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी है जो फ्रंटलाइन काम्पैक्ट यूनिट की कमान संभाल रही है। फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली भी वह पहली महिला अधिकारी है। भारत की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और थलसेना एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं।रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी। साथ ही उन्हें पेंशन और सभी भत्ते भी मिलेंगे। 1992 में पांच साल के लिये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। इसके बाद इस सर्विस की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 2006 में शार्ट सर्विस कमीशन को 14 साल कर दिया गया। भारतीय सेना अब महिलाओं को सशत्र बल में नियुक्ति के लिए उनके लिए तय की गई नीतियों को लागू कर प्रोत्साहित करती है। इसके लिए महिलाओं के लिए आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिटरी नर्सिंग सेवाओं के लिए परमानेंट कमिशन को मंजूरी दी गई है। अब 11 आर्म्स एंड सर्विसेज में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमिशन मिलता है। जिनमें आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आर्डनेंस कोर, आर्मी एडुकेशन कोर, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, इंजीनियर कोर, सिगनल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मकैनिकल कोर, इंटेलीजेंस कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, रीमाउंट एंड वेटनरी कोर आदि शामिल हैं।परमानेंट कमिशन के बाद महिला अधिकारी इंडियन आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में शामिल आर्टिलरी का हिस्सा बनने लगी है। सेना आर्टिलरी की लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5,000 अधिकारी हैं। आर्टिलरी में शामिल महिला अधिकारियों की बोफोर्स, होवित्जर, के-9 वज्र जैसी तोपों पर भी 2023 में तैनाती की अनुमति दी जा चुकी है।वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्तियों में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पुरुष और महिला जवानों की हथियारों और सेवाओं के लिए तैनाती में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है। सभी की पोस्टिंग सेना की जरूरतों के अनुसार की जाती है। भारतीय सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमिशन के लिए 23 नवंबर 2021 को एक जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोग्रेशन पॉलिसी लाई गई थी। इसके जरिए महिलाओं को हथियारों व अन्य सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

संपादकीय

गजा में भूख से मरते मासूम

हमास के हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया ने अब बेहद त्रासद रुख अख्तियार कर लिया है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तमाम मानवीय तकाजों को ताक पर रख दिया गया है और प्रभावित इलाकों में लोग भूख से मरने को मजबूर हैं। इस बात की कोई फिक्रनहीं दिखती कि अब एकतरफा हो चुके युद्ध में मरने वाले निदीष और मासूम बच्चे हैं। गाजा में इजराइल के हमलों में जो लोग मारे जा रहे हैं, वह एक पक्ष भर है। इसके समांतर त्रासद और भयावह यह है कि इजराइल ने गाजा के प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नतीजा यह है कि अब वहां लोगों और खासकर बच्चों के मारे जाने की बड़ी वजह भुखमरी बन गई है। गाजा के अस्पतालों में हजारों की तादाद में कुपोषण के शिकार ऐसे बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिन्हें जान बचाने के लिए पेट भरने लायक खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी जारी की थी कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली, तो सिर्फ दो दिनों के भीतर चौदह हजार बच्चों की जान जा सकती है। दरअसल, करीब दो महीने से इजराइल ने सभी खाद्य सहायता, दवा और अन्य सामान के गाजा के युद्ध प्रभावित इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जहां करीब बीस लाख फिलिस्तीनियों की आबादी रहती है। गाजा में रहने वाले ये लोग पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भर हैं, क्योंकि इजराइली हमले ने उस इलाके की सभी खाद्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह कर दिया है। जाहिर है, अब गाजा में अकाल का खतरा भी सामने खड़ा है। मगर अफसोसनाक यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयास इजराइल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गाजा में इजराइली हमले में अब तक साठ हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, जिनका हमास या आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं था। सवाल है कि हमास के जिस हमले को मानवता के खिलाफ बता कर इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, उसमें मासूमों को मार कर क्या हासिल हो रहा है।

भारत में कृषि संकट और खेत मज़दूरों की बदलती प्रकृति खून पर भारी सिंदूर-व्यापार!

विक्रम सिंह

महाराष्ट्र के नांदेड जिले की मुखेड तालुका के अंबुलगा गाँव के खेत मज़दूर माणिक घोंसटेवाड को साल के कुछ महीनों में ही खेतों में काम मिलता है। उनको जून-जुलाई में सोयाबीन या कपास की बुआई, अगस्त-सितंबर में निराई (हाथ से या कीटनाशकों से), और दिसंबर-जनवरी में कटाई के दौरान ही रोज़गार मिलता है। लेकिन यह काम भी निरंतर नहीं होता और इन महीनों के भी कुछ ही दिन काम मिल पाता है। गाँव और आसपास के इलाकों में कृषि में काम के दिन सीमित होने के कारण उनके परिवार का गुज़ारा मुश्किल हो जाता है। साल के बाकी दिन वह दिहाड़ी के लिए कई तरह के काम करते हैं, जैसे : सिर पर समान ढोने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, निर्माण मज़दूर का काम। मूलता वह हर काम करता है, जो उपलब्ध हो। खेती और कटाई के मौसम में भी वह गैर कृषि काम में दिहाड़ी करके अपनी अजीविका जुटाने का प्रयास करता है, जिससे कि परिवार का खर्च निकल सके। वह मनरेगा का भी नियमित मज़दूर हैं, मगर वहां काम मिलना सरकार और पंचायत अधिकारियों की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। पशुपालन से भी परिवार को कुछ आय होती है। इसी गाँव के मारोती शिवराम मिश्किरे खेती के अलावा ड्राइवर का भी काम करते हैं। साथ ही, वे सूअर पालते हैं, जो उनके घर की आय का एक अतिरिक्त स्रोत है। इस गांव में किए गए सर्वेक्षण के दौरान मिले खेत मजदूरों के काम के विभिन्न रूपों के ये दो उदाहरण ग्रामीण भारत में रोजगार और ग्रामीण मज़दूरों की बदलती परस्थितियों को दर्शाते हैं। इस बदलाव के कई कारण हैं, जिनमें मज़दूरों का विस्थापन करने वाली मशीनों का अंधाधुंध उपयोग और खेतों पर निर्भर मजदूरों की बढ़ती संख्या शामिल है। हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है, जहां मजदूरों की एक बड़ी संख्या है, जिन्हें ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं मिलता और न ही पलायन करने के बाद शहरी केंद्रों में सुनिश्चित रोजगार मिलता है। भारत में बढ़ता कृषि संकट इस स्थिति का मूल कारण है।

भारत में ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जो 2017-18 में 44.1% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 48.17 करोड़ थी । इसमें से 72 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और इसमें से आधे से अधिक यानी 54.6 प्रतिशत या 26.3 करोड़ कृषि से जुड़े रोजगार में लगे हुए है। कृषि में काम करने वाले लोगों में मुख्य रूप से किसान और खेत मजदूर आते है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इन दोनों समूहों के बीच में ज़मीन के मालिकाना हक़ की व्यवस्था एक मौलिक अंतर है, विशेष रूप से 'मालिकाना अधिकार', 'लीज का अधिकार' और 'भूमि अनुबंध' का होना या न होना। जहां एक तरफ एक किसान के पास ज़मीन होती है, नहीं तो लीज या फिर अनुबंध होता है, वहीं दूसरी तरफ खेत मज़दूर भूमिहीन होते है और दूसरों की ज़मीन पर दिहाड़ी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान भी मजबूरी में दूसरों के खेतों या अन्य कामों में मजदूरी करते हैं, जिससे किसान और मजदूर के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। खेत मजदूर ग्रामीण सर्वहारा वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो कृषि उत्पादन में लगे हुए हैं। वह ग्रामीण भारत में सबसे दबे-कुचले और हाशिए पर रहने वाला वर्ग हैं। खेत मजदूर सभी संसाधनों से वंचित हैं और उनमें से भी ज्यादातर भूमिहीन है, उनके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं है और वे आजीविका के लिए अपने श्रम पर निर्भर हैं। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के चलते वह शोषण का शिकार होते है और ज़मींदारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करने को मजबूर हैं। ज्यादातर खेत मज़दूरों के पास घर तक नहीं होते, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वे न सिर्फ़ आर्थिक रूप से शोषित होते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका शोषण होता है और हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं, जहाँ उन्हें भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिला खेत मजदूरों को लैंगिक भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है और पुरुषों के मुकाबले समान काम के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है। व्यवस्थित उत्पीड़न के कारण खेत मज़दूर समग्र विकास की मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन में गरीबी और गैर-बराबरी का कुचक्रबना रहता है। ऐतिहासिक रूप से यह वर्ग शिक्षा से दूर रहा है और वर्तमान में भी इनके बच्चों को आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास में बाधा आती है। संगठन और यूनियनों की कमी के कारण सामूहिक ताक़त, राजनीतिक चेतना और संघर्षों से ये मज़दूर अपरिचित रह जाते हैं। भारत के बंधुआ मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा खेत मज़दूरों का रहा है। बंधुआ मजदूरी सामाजिक और आर्थिक शोषण का सबसे भयानक रूप है। यह गुलामी कर्ज़ और कर्ज़ के बोझ से पैदा होती है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता था, जैसे गुजरात में 'हाली', बिहार में 'कमिया', मध्य प्रदेश में 'हरवाहा', आंध्र प्रदेश में 'गोठी', कर्नाटक में 'जीथा' आदि। हरित क्रांति के बाद कई प्रवासी मजदूरों को अपनी मजबूरियों के कारण जमींदारों द्वारा लगाई गई तरह-तरह की पाबंदियों को मानना पड़ा, जिससे वे बंधुआ मजदूरों जैसी हालत में पहुँच गए। ग्रामीण सामंती संरचना के अंतर्गत भूमिहीन परिवार आज भी अपनी रोज़ी- रोटी के लिए जमींदारों और अमीर किसानों पर निर्भर हैं और उनके हुक्म पर काम करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कानूनी तौर पर बंधुआ प्रथा समाप्त हो चुकी है, पर बेरोज़गारी के चलते मजदूरों को कम मजदूरी वाले अनुबंधों में जकड़ा जाता है। आज़ादी के बाद यह वर्ग सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वर्ग है। खासकर पिछले तीन दशकों में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद खेतिहर मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 1960 से 2001 तक के चार दशकों में कुल कृषि कार्यबल में खेत मजदूरों से ज्यादा किसान थे। लेकिन, 2011 की जनगणना में पहली बार यह रुझान बदला। जनगणना से पता चला कि कुल कृषि कार्यबल में किसानों की हिस्सेदारी आधे से कम (लगभग 45%) रह गई थी, जबकि खेत मजदूरों की हिस्सेदारी करीब 55% थी। असल संख्या में किसानों की कुल संख्या 11,86,69,264 थी, जबकि खेतिहर मजदूरों की संख्या 14,43,29,833 थी। 1961 में हर 100 किसानों पर 33 खेत मजदूर थे, लेकिन 2011 में यह संख्या बढ़कर हर 100 किसानों पर 121 मजदूर हो गई। खेत मजदूरों की संख्या बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है किसानों का गरीब होना, खासकर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद। इन नीतियों के कारण कृषि को मिलने वाली सरकारी मदद कम हो गई, जिससे खेती की लागत बहुत बढ़ गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या फसल की खरीद की कोई गारंटी नहीं रही। इस वजह से कृषि की पूरी प्रक्रिया ज्यादा अनिश्चित हो गई है। पहले किसानों के लिए सिर्फ मौसम की ही अनिश्चितता थी - वे सूखे और बारिश से डरते थे, लेकिन अब बाजार की अनिश्चितताएँ प्रकृति से भी ज्यादा कठिन और कठोर हैं। जब पूरी प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य मुनाफा ही होता है, तो इसमें खेत मजदूरों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं बचता। लगातार बने रहने वाला कृषि संकट छोटे और सीमांत किसानों को अपनी खेती से विस्थापित कर रहा है और वह किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहें है, क्योंकि अब खेती उनके परिवार का पेट नहीं पाल पा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आँकड़ों पर आधारित अध्ययन बताते हैं कि लाखों छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, खेती छोड़नी पड़ रही है और वह मजदूरों की कतारों में शामिल हो रहें हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि छोटे कारीगर भी अपना रोजगार खो रहें हैं और उन्हें खेत मजदूर के रूप में या अन्य छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वर्तमान में खेत मजदूरों की संख्या किसानों से ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि ज्यादा खेत मज़दूरों की खेती पर निर्भरता बढ़ गई है। खेत मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही, मशीनों और प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध इस्तेमाल ने कृषि में काम के दिन और कम कर दिए हैं। ग्रामीण भारत में बढ़ती बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में बढ़ते संकट और आमदनी की कमी के कारण युवाओं को अपनी जीविका के लिए पलायन करना पड़ रहा है। शहरों में आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी एक जटिल स्थिति पैदा कर रही है। इन हालातों में, बड़ी संख्या में मजदूरों को गैर-कृषि क्षेत्रों में काम ढूँढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति ग्रामीण भारत के मजदूरों को अपने परिवार के गुजारे के लिए तरह-तरह के काम करने पर मजबूर कर रही है। ज्यादातर खेत मजदूर पूरे साल किसी एक काम तक सीमित नहीं रहते। लगभग सभी ग्रामीण मजदूर अलग-अलग अनुपात में खेती के काम में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, वह सब समय-समय पर कई तरह के काम करते हैं - जैसे मनरेगा का काम, ईंट भट्टे पर मजदूरी, खेतों में मजदूरी या फिर आस-पास के छोटे शहरों में औद्योगिक काम। खेती में काम करने वाले खेत मजदूर और गैर-कृषि काम करने वाले मजदूर अब मजदूरों के दो अलग-अलग समूह नही रह गए हैं। खेत मजदूर कृषि के साथ-साथ कई तरह के गैर-कृषि काम भी करते हैं, जिसमें शहरी इलाकों में पलायन करके काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। फिर भी, ये मजदूर आंशिक रूप से गाँव और खेती से जुड़े रहते हैं और शहरी मजदूर वर्ग से कई मायनों में अलग हैं। इसका मतलब यह है कि गाँवों के बड़ी संख्या में मजदूर अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन वे खेती से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर खेत और ग्रामीण मजदूरों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। कम आमदनी और बढ़ती बेरोजगारी के बीच, खेत मजदूरों का जीवन कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक संस्थाओं पर निर्भर है। परंतु नवउदारवाद समर्थक पूँजीवादी ताकतें इन कल्याणकारी संस्थाओं के खिलाफ हैं। केरल की वाम मोर्चा सरकार को छोड़कर, पूरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों का तेजी से निजीकरण हो रहा है। सभी तरह की पेंशन योजनाओं को सीमित करने की वजह से ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। स्थिति इतनी खराब है कि मनरेगा के तहत रोज़गार के अधिकार को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। संकट इतना गहरा हो चुका है कि खेत मजदूर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं, जो उनकी भयावह स्थिति को दर्शाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से अब तक कुल 40,685 खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है। जिस समय खेत मजदूरों के रोज़गार और रहन-सहन में बदलाव आ रहा है, तब गाँवों में एक नए अमीर वर्ग का भी उदय हुआ है।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की स्थायी नीति बने

आशीष जोशी

परीक्षाएं समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मावकाश भी शुरू हो गया है। जुलाई में सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है कि क्या इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो पाएंगे। यह प्रश्न इसलिए भी कि पिछले सात साल से इस श्रेणी के शिक्षक अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में नवनियुक्त शिक्षक भी हैं, जिनका नियुक्ति के बाद एक बार भी तबादला नहीं हुआ। यों तो तबादला करना या न करना सरकार का विशेष अधिकार है लेकिन सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ही तबादलों से वंचित करने पर खुद शिक्षक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इन शिक्षकों की मांग है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएं। शिक्षकों का यह भी कहना है कि खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह चुके हैं कि 15 मार्च के बाद तबादले खोले जाएंगे। हालांकि यह तिथि भी निकल चुकी है। पिछले कांग्रेस राज में भी पांच साल तक तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों की मांग करते रहे, लेकिन तब भी तबादले नहीं हुए। अंतिम बार वर्ष 2018 में ही इस श्रेणी के शिक्षकों के तबादले हो सके थे। तब भी बड़ी संख्या में एकल महिला, विधवा,

परित्यक्ता, दिव्यांगों के अलावा गंभीर रोग से ग्रसित आवेदकों को राहत मिली थी। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। शिक्षकों के तबादले, नीति नहीं होने की आड़ में ही अटकाए जाते रहे हैं। कई कमेटियां व मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन के बावजूद तबादलों को लेकर कोई कारगर नीति नहीं बन सकी है। वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2021 तक करीब आधा दर्जन कमेटियां तबादला नीति पर सुझाव देने को लेकर बनी लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दरअसल तबादलों के लिए डिजायर संस्कृति ने ही कोई नीति नहीं बनने दी। प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं। इनमें से 72 हजार शिक्षक कई वर्षों से 'डार्क जोन' वाले जिलों में कार्यरत हैं। वे अपने गृह जिले के आसपास आना चाहते हैं। अब शिक्षक संगठनों ने तबादले नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में अगले महीने तक तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो फिर नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। सरकार को शिक्षक संगठनों से भी विचार-विमर्श कर तबादलों की स्थायी नीति बनानी चाहिए ताकि असमंजस दूर हो सके।

स्वामित्वाधिकारी, मुद्रक , प्रकाशक व संपादक सरोज चौधरी द्वारा न्यू लोक भारती प्रेस, वार्ड 10 कोकर औद्योगिक क्षेत्र कोकर रांची से मुद्रित तथा ई -37, अशोक विहार रांची से प्रकाशित, संस्थापक संपादक :स्व. राधाकृष्ण चौधरी
प्रबंध संपादक : अरूण कुमार चौधरी, फोन: 9471170557/08084674042, ई-मेल : Divyadinkarranchi @ gmail.com,RNI Regd. No. : JHAHIN/2013/54373Postal Registration No. : RN-11/2012)

संक्षिप्त समाचार

श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का दीवार गिराए जाने से महमदा और गढीरामपुर गांव के बीच तनाव, पुलिस कर रही कैंप

देर रात बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, कर रही मामले की जांच

मामला नयारामनगर थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का

दिव्य दिनकर संवाददाता

मुंगेरः मुंगेर जिले के नयारामनगर थाना अंतर्गत श्री राम जानकी ठ-ाकुरबाड़ी महमदा का निमार्णाधीन पक्का दीवार असामाजिक तत्वों के द्वारा गिराए जाने से गढीरामपुर तथा महमदा पाटम गांव के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. रविवार की देर रात्रि असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है. घटना की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैलते हैं भारी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए हैं. घटना की सूचना जैसे ही गढ-ीरामपुर गांव के लोगों को मिली, वैसे ही भारी संख्या में लोग दुर्गा मंदिर गढ-ीरामपुर के समीप एकत्रित हो गए. वहीं दूसरी ओर महमदा पाटम के लोग भी भारी संख्या में चैती दुर्गा मंदिर महमदा के समीप जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही नयारामनगर थानाध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद सिंह स्थल पर पहुंचे. मामले के गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने वस्तु स्थिति से मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद तथा सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद को अवगत कराया. इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. गढीरामपुर गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को गढीरामपुर दुर्गा मंदिर के समीप ही रोक दिया. श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी महमदा के समीप जाने से मना कर दिया. इसलिए हम लोग वहां नहीं गए. गढीरामपुर गांव के लोगों ने महमदा पाटम के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. सूत्रों से पता चला है कि समय पर अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद महमदा पाटम और गढीरामपुर गांव के बीच जंग छिड़ सकती थी. जिसमें अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था. फिलहाल सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में पुलिस श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के समीप कैंप कर रही है और लोगों को समझने का प्रयास भी किया जा रहा है. बताया जाता है कि पुलिस यह पता करने में लगी है कि श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का दीवार किन-किन असामाजिक तत्वों के द्वारा गिराया गया है. वहीं, महमदा पाटम के लोगों का कहना है कि गढ-ीरामपुर गांव के असामाजिक तत्वों के द्वारा ही श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का दीवार रात्रि में गिराकर यह तनाव पैदा किया गया है. वहीं दूसरी ओर गढीरामपुर गांव के लोगों ने महमदा पाटम गांव के लोगों पर श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी का दीवार एक सोची समझी साजिश के तहत गिराए जाने का आरोप लगा रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है तथा तनाव को देखते हुए पुलिस गढीरामपुर एवं महमदा गांव में कैंप कर रही है. इधर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस घटना स्तर पर कैंप कर रही है तथा मामले की छानबीन भी कर रही है. उन्होंने कहा कि दीवार गिरने वाले सामाजिक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे.

दानिका के संस्थापक यमुना राम का तीसरी पुण्यतिथि पर काव्य गोष्ठी 30 मई को को आयोजित किया जाएगा

रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिला मुख्यालय की महत्वपूर्ण सांगीतिक संस्था दानिका संगीत महाविद्यालय के तत्वावधान में दानी विगहा स्थित दानिका के प्रधान कार्यालय में दानिका के संस्थापक यमुना राम जी की तीसरी पुण्यतिथि 30 मई को मनाया जाएगा।इस आशय की जानकारी देते हुए दानिका के डायरेक्टर डॉ रविंद्र कुमार एवं प्र-वक्ता सुरेश विद्यार्थी ने बताया कि पुण्यतिथि के अवसर पर काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।विदित हो कि यमुना राम जी उच्च कोटि के कलाकार एवं औरंगाबाद में सांगीतिक परंपरा के संवाहक थे।दानिका परिवार की स्थापना कर उन्होंने संगीत की ऐसी परिभाषा गढ़ी जिसकी चर्चा आज राष्ट्रीय स्तर पर होती है। दानिका घराना के माध्यम से सांगीतिक परम्परा को आमजन के सामने लाने का प्रयास किया था।पुण्यतिथि पर स्थानीय कवियों, साहित्यकारों,सांगीतिक कलाका-रों,बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकताओं की विशेष सहभागिता होगी।विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा।

बमेन्द्र ने विशेष विकास शिविर का लाभ लेने के लिए अनु. जाति के परिवारों को किया जागरूक

रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- बिहार सरकार द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन अनु. जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अनु. जाति, अनु.जनजाति विशेष विकास शि-विर का आयोजन हर पंचायत के चिन्हित टोलों में किया जा रहा है।शिविर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों से आवेदन लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।शिविर से वंचित लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए औरंगाबाद की स्वयं सेवी संस्था पथ प्रदर्शक के संस्थापक सह सचिव बमेंद्र कुमार सिंह प्रयासरत हैं। शनिवार को बमेंद्र कुटुंबा प्रखण्ड अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत के दसवत बिगहा गांव के अनु.जाति परिवारों से मिले।सरकार की विशेष विकास शि-विर से वंचित परिवार से मिलकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किये,साथ ही सहयोग का आश्वासन दिए।सरकार द्वारा बाइस सरकारी योजनाओं के लिए इन दिनों अनु.जातियों के चिन्हित टोलों में विशेष विकास शिविर लगा कर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है,जिसपर सरकार द्वारा त्वरित करवाई करते हुए लाभ दिया जा रहा है।मुख्य रूप से योजनाओं में पक्का गली - नाली, नल जल योजना,राशन कार्ड,आयुष्मान कार्ड,आधार कार्ड,जन्म प्रमाण पत्र,मृत्यु प्रमाण पर,श्रम कार्ड,वासगीत पर्चा,जॉब कार्ड,विद्युत कनेक्शन इत्यादि शामिल है।दसवत बिगहा के अनु जाति के कुल 48 परिवार हैं।लाभुकों ने बमेंद्र से नल जल योजना,पक्का गली - नाली निर्माण,इंदिरा आवास,राशन कार्ड,आधार कार्ड,जॉब कार्ड ,वासगीत पर्चा इत्यादि के लिए कहा जिसे बनवाने के लिए बमेन्द्र सरकारी अधिकारियों से मिल कर प्रयास कर रहे हैं।इस अवसर पर टीम पथ प्रदर्शक के सिमोद सिंह,अमरेंद्र कुमार सिंह,रविदास टोला दसवत बिगहा के रणविजय राम,चन्द्रधन राम,मनोज राम,कुंदन कुमार,पूनम देवी,सुशीला देवी,चंद्र देवी,धनवती देवी,दुखी राम इत्यादि उपस्थित थे।

रेलमंत्री के कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया गया उचित सम्मान

जमालपुर की आम जनता और रेल यात्रियों के अरमानों पर रेल मंत्री ने फेरा पानी : राजेश रमण

दिव्य दिनकर बिहार उप-प्रभारी पवन कुमार चौधरी

जमालपुर। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल करार देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसे चुनावी जनसभा का मंच करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्र-कोष्ठ के मुंगेर जिला अध्यक्ष राजेश रमण उर्फ राजू यादव ने कहा कि विकास की राह तक रहे एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर के साथ केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सौतेला व्यवहार करते हुए ना तो जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिया गया और ना ही जमालपुर में रेलवे से जुड़े किसी भी बड़े योजनाओं का शुभारंभ किया गया। जमालपुर में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम के दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया। केंद्रीय रेलमंत्री के समक्ष जमालपुर के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकताओं के द्वारा जमालपुर रेल कारखाना के विकास तथा जमालपुर में रेलवे से जुड़ी विभिन्न विषयों पर मांग पत्र देने के साथ-साथ माननीय रेल मंत्री के साथ वार्ता के लिए रेलवे के अधिकारियों से गुहार लगाई गई थी। परंतु, रेलवे मंत्रालय की ओर से विपक्षी नेताओं को वार्ता के लिए समय नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी

सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जब रेल मंत्री से वार्ता को लेकर मांग की तो रेलमंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जमालपुर रेल क्षेत्र के विकास को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मांग पत्र में जिन मुद्दों को उठाया गया, उनमें से एक भी मुद्दे पर रेलमंत्री ने अपनी भाषण में जिक्र नहीं किया। ना तो जमालपुर कारखाना को निर्माण का-रखाना का दर्जा दिया गया, ना ही जमालपुर में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर कोई कदम उठाया गया और ना ही जमालपुर रेल क्षेत्र के विकास को लेकर किसी प्र-कार की घोषणा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महज 350 करोड़ रुपए का घोषणा कर जमालपुर वासियों के समक्ष एक नया जुमला पेश किया गया है। जिसे आगामी विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी जुमला बताकर खारिज कर दिया जाएगा। रेल मंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजाम में भी भारी कमी दिखी। केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के अलावा मुंगेर जिला के तारापुर से ताल्लुक रखने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय से ताल्लुक रखने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा द्वारा जमालपुर रेल कारखाना के विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों को रेलमंत्री ने सीधे-सीधे खारिज कर, उन नेताओं के दावों और वादों पर जोरदार तमाचा दिया है।

17 जून को पटना में आयोजित होगी कानू अधिकार रैली,गोह में हुई तैयारी बैठक

सरकार से SC/ST में शामिल करने की मांग की गई

रिपोर्ट - अमरेन्द्र कुमार सिंह

गोह (औरंगाबाद)आगामी 17 जून को पटना के मिलर उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाली कानू अधिकार रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में गोह प्रखंड के बिनोबा बिगहा गांव स्थित डॉ. मुकेश कुमार के आवास पर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन समाजसेवी गौरी प्रसाद शंकर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अजय कानू ने कहा कि कानू समाज आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। समाज के लोगों के साथ लगातार हो रही मारपीट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने मांग की कि कानू समाज को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में शामिल कर उनके लिए अत्याचार निवारण कानून बनाते हुए लागू किया जाए, ताकि उन्हें न्याय और संरक्षण मिल सके। अजय कानू ने कहा कि आज तक लोकसभा, राज्यसभा, बोर्ड या किसी निगम में कानू समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि उनकी जनसंख्या तीन प्रतिशत (करीब तीस लाख) है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि किसी पार्टी द्वारा हमारे समाज के योग्य प्रतिनिधि को टिकट दिया गया, तो कानू समाज एकजुट होकर उस पार्टी को जिताने का काम करेगा।यदि किसी राजनीति पार्टी टिकट नही देगा तो

हमलोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला राज्य कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया है। बैठक में उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में प्रमंडल अध्यक्ष कृष्णा कानू, औरंगाबाद प्रभारी एवं पूर्व मुखिया मुन्ना कुमार जहानाबाद जिला अध्यक्ष नवल कानू टेकारी से आये अरबिंद कानू , रणविजय कुमार, मनोज कुमार, डॉ. मुकेश कुमार, रंजू देवी, जयराम कानू, विमलेश व्यास, किशोरी प्रसाद, रामाशीष कानू, दुर्गा प्रसाद, मनदीप कानू, रमाकांत कानू, सुरेंद्र कानू, संतोष कानू, राजेंद्र साव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में आगामी 17 जून को पटना में आयोजित होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का संकल्प लिया और सरकार से कानू समाज के हक-अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया।

2005 के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिया हडियाही नहर पर ध्यान- डॉ सुरेश पासवान

रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पासवान ने कहा है कि किसानों के लिए अति महत्वाकांक्षी बटाने शीर्ष परियोजना हडियाही नहर के अधूरे काम को पूरा कराने के लिए सन 2005 के बाद से अभी तक उस छेत्र के सांसद हो या विधायक किसी ने भी ईमानदारी से उस नहर के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया जिसका नतीजा है कि पैतालीस बरसों के बाद भी हडियाही नहर अपने पड़ाव पार पड़ी हुई है। बटाने शीर्ष परियोजना हडियाही नहर के निर्माण का परिकल्पना उत्तर कोयल नाहर के दक्षिणी इलाके का यह असिंचित भूमि को सिंचित करने का प्लान बनाया गया था, औरंगाबाद ज़िला के नवीनगर कुटुम्बा एवं देव प्रखण्ड के लाखो हेक्टेयर भूमि को इस नहर के बन जाने से सुखी एवं बंजर भूमि में न सिर्फ.किसानों के खेतों में पानी मिलता बल्कि इलाके का पिछड़ापन तथा उग्रवाद जैसी समस्या से भी सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता और इस इलाके के किसान और मजदूर दोनों को पलायन करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। डॉक्टर पासवान ने कहा है कि सरकार की उ-दासीनता के साथ साथ इस क्षेत्र के जो भी जिस दल के सांसद या विधायक रहे हैं उन्होंने अपने जनता के प्रति जवाबदेही को निभाने में उदासीनता दिखाया है ।जिसके चलते ही बँटाने शीर्ष परियोजना हडियाही नहर का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है ।अभी भी समय

है कि संयुक्त रूप से सांसद व विधायक को बिहार सरकार ,झारखंड सरकार,और केंद्र सरकार के समक्ष इस परियोजना को पूरा करने के लिए जोरदार आवाज उठाना चाहिए और यदि सरकार आवाज को अनसुनी करे तो किसानों को एकत्रित कर के आंदोलन की भी तैयारी करना चाहिए। ताकि बरसों से लंबित इस नहर के निर्माण कार्य को पूरा कराकर के बँटाने राइट एवं लेफ़्ट कैनाल से किसानों के असिंचित भूमि को सिंचित किया जा सके।

महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार

ओबरा प्रखंड के बेल ग्राम में महिलाओं से संवाद, सशक्तिकरण पर दिया जोर

रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिले के ओबरा प्र-खंड अंतर्गत बेल ग्राम में ₹महिला संवाद₹ कार्यक्रम का आयोजन जी-विका के चन्द्रमा ग्राम संगठन के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार, श्री श्रवण कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिलाधिकारी, औरंगाबाद, श्री श्रीकांत शास्त्री सहित जीविका से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं झ श्रीमती रंजीती देवी, उषा देवी, चन्द्रावती कुमारी, निशा सिंह, रानी कुमारी आदि द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए की गई। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने बिहार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं झ जैसे कन्या उत्थान योजना, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, तथा शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं झ का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा एवं रोजगार तक विभिन्न चरणों

में आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में बेटियों को जन्म के समय तथा सम्पूर्ण टीकाकरण उपरांत 2000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय जाने पर पोशाक एवं साइकिल योजना के तहत प्रोत्साहन राशि, तथा मैट्रिक, इंटर व स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होने पर छात्र-ावृत्ति की सुविधा भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। साथ ही, सरका-री सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य में 10,63,000 से अधिक जी-विका स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से 1 करोड़ 35 लाख से अधिक परिवार आजीविका से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश के किसी अन्य राज्य में इतनी बड़ी संख्या में महिला समूहों का गठन नहीं हुआ है, जो अपने आप में बिहार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को पंचायत, नगर निकाय, पुलिस, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो नए निर्णय लिए गए हैं। जीविका निधि कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना, सभी प्रखंड कार्यालयों की सफाई व्यवस्था जी-विका समूहों को सौंपना। आगामी योजनाओं के अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पोखरों में मत्स्य पालन, प्रखंड कार्यालयों में कैंटीन संचालन सहित अन्य कार्यों को भी जीविका समूहों को दिये जाने की योजना है। शहरी क्षेत्रों में भी जीविका के माध्यम से गरीब एवं वंचित परि-वारों को संगठित कर उनके उत्थान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने जीविका द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका सशक्त होना राज्य की समग्र प्रगति के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका झ श्री पवन कुमार, प्रबंधक संचार झ मो. अनवर हुसैन, प्रबंधक संस्था निर्माण एवं क्षमता वर्धन झ श्री रणंजय कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, ओबरा झ श्रीमती सविता कुमारी, क्षेत्रीय समन्वयक झ श्री अरुण कुमार एवं श्रीमती बिमल कुमारी, सामुदायिक समन्वयक झ श्री भरत कुमार एवं श्रीमती अवंती कुमारी की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उपस्थित जनसमूह ने सरकार की योजनाओं एवं प्रयासों की सराहना की।

डॉ.देवराज सुमन के डीएसडब्ल्यू बनने पर स्वागत सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन

शीतल आश्रम यादव छात्रावास पूरबसराय के प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम

दिव्य दिनकर संवाददाता

मुंगेर : मुंगेर के स्थानीय शीतल आश्रम यादव छात्रावास पूरबसराय, मुंगेर के प्रांगण में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला मुंगेर की तरफ से डॉक्टर देवराज सुमन को मुंगेर विश्वविद्यालय का डीएसडब्ल्यू नियुक्त किए जाने पर स्वागत सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल भूषण एवं संचालन संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सुमन ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए नरेश सिंह यादव ने कहा की डॉक्टर देवराज सुमन की पहचान जमालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व समाजवादी नेता प्रो० स्वर्गीय भगवत प्रसाद यादव जी के पुत्र के रूप में होती है।हम ईश्वर से कामना करते हैं कि छात्रों एवं समाज के निचले पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए यह इतना अधिक कार्य करें की भागवत बाबू की पहचान प्रोफेसर डॉक्टर देवराज सुमन के पिता के रूप में हो। अखिल भारतीय यादव महासभा मुंगेर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सुमन ने डॉक्टर देवराज सुमन को डीएसडब्ल्यू नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि यूं तो डॉक्टर देवराज सुमन के कार्य क्षेत्र में मुंगेर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज आते हैं लेकिन मैं आर० डी०एन०डी०जे० कॉलेज का पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते इनसे कहना चाहूंगा कि जब मैं आरडी एन्ड डीजे कॉलेज मुंगेर का छात्र था तो उस समय के प्राचार्य अचार्य कपिल थे वह कॉलेज का स्वर्णिम काल था। लेकिन आज कॉलेज का सभी भवन जर्जर स्थिति में है ना तो विद्यार्थियों को खेलने के लिए कॉमन रूम उपलब्ध है ना ही साइकिल लगाने के लिए साइकिल स्टैंड। अध्ययन कक्ष भी काफी जर्जर हो चुका है। अतः मैं इनसे मांग करता हूं कि वहां की व्यवस्था में

ये यथाशीघ्र सुधार लाएं।

मुख्य अतिथि डॉक्टर देवराज सुमन ने अपने संबोधन में कहा की हमें जो जिम्मेवारी दी गई है उसका निर्वाह हम ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। छात्रों के हित में मैं पूर्व से ही कार्य करते आ रहा हूं अब मुंगेर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अपने पठन-पाठन के कार्यों के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। जहां तक डीजे कॉलेज के विकास का संबंध है मैं यथाशीघ्र वहां के जर्जर भवनों एवं चार दिवा-री का जिन्नौद्धार कराकर बंद पड़े बॉयज कॉमन रूम, साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड को शीघ्र चालू कराऊंगा। कार्यक्रम को संस्था के प्रधान महासचिव बालेश्वर प्रसाद यादव, नवीन कुमार यादव, आदर्श कुमार राजा, दिनेश कुमार यादव, मनीष कुमार, मोहम्मद शकील अहमद, प्रो० बम बम राय, डॉ रणधीर राय, अरविंद कुमार यादव, जयप्रकाश यादव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार यादव, सरवन कुमार, रंजन यादव, विजय यादव, युगल किशोर यादव, पप्पू यादव सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन भाषण करते हुए संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल भूषण ने बड़ी संख्या में उपस्थित प्रबुद्ध जनों के के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर देवराज सुमन को बधाई देते हुए उनके लिए मंगलमय जीवन की कामना की।

विष्णु धाम के त्रि संकट निवारण वृक्ष के पास बट सावित्री पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति

रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिले का वैष्णवी परंपरा का प्रमुख तीर्थ स्थल विष्णु धाम के प्रांगण में अवस्थित त्रिसंकट निवारण वृक्ष के पास वट सावित्री पूजा के मौके पर 26 मई को श्रद्धालु भक्त विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस संदर्भ में विष्णु धाम के वर्तमान महंत बाल्कानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि मोक्षदायिनी पुनपुन एवं पुण्यदायिनी बटाने के संगम तट पर अवस्थित विष्णु धाम के प्रांगण में यह अत्यंत ही दुर्लभ वृक्ष है जो एक ही जगह पर तीनों वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बट वृक्ष, पीपल वृक्ष एवं पांकड का वृक्ष तीनों का एक साथ एक जगह पर प्रस्फुटित होकर वृक्ष का विशाल रूप बनना अत्यंत थी दुर्लभ संयोग का परिचायक है। पूर्व के महंत ने इस स्थान का नाम त्रि संकट निवारण स्थल बताया और इस त्रि संकट निवारण वृक्ष के नीचे बट सावित्री व्रत के दिन किए गए पूजा पाठ विशेष फलदाई होते हैं। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी ने बताया कि प्रकृति का अद्भुत तीर्थ स्थल विष्णु धाम है । जिसके परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की अलौकिक एवं दिव्य मूर्तियां स्थापित है। इसी कड़ी में यह स्थल भी है जिसे त्री संकट निवारण वृक्ष के नाम से जाना जाता है जो त्रिदेव का प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश है।तीन लोक का प्रतीक है इनके पूजा से तीन ताप दैहिक दैविक भौतिक से मुक्ति मिलती है। तीन दोषों का निवारण होता है शरीर में फैलने वाले जो तीन प्रकार के वात पित्त कफ जैसे दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है यह अत्यंत ही दुर्लभ जगह है। बट सावित्री पूजा के दिन श्रद्धालु महिलाएं यहां विशेष पूजा अर्चना करती हैं शास्त्रों में वर्णन है भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्ष में पीपल हू इस दिन तांबे के लोटे में जल रखकर कच्चा दूध मिलाकर बताशा डालकर इस वृक्ष के नीचे अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है महिलाएं कच्चा सूता लपेटकर तीन परिक्रमा करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है।घर में सुख शांति बरकरार रहती है।

अपने मनपसंद नेता की तस्वीर न लगने पर भिड़े बीजेपी वर्कर, पीछे से भीड़ लगाती रही भारत माता की जय के नारे

समस्तीपुर: समस्तीपुर के रोसड़ा के भिरहा में बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मंच के पीछे एक बैनर लगा था, लेकिन बैनर में विधान पार्षद तरुण चौधरी का फोटो नहीं था....इसके अलावा बीजेपी की जिलाध्यक्ष नीलम सहनी को तस्वीर को भी बैनर पर छोटा करके लगाया गया था....जबकि बैनर पर रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। इस वजह से बीजेपी के एक गुट के कार्यकताओं में आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद मुख्य मंच के सामने ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए.....हालांकि इस दौरान भी पीछे से वर्कर भारत माता की जय के नारे भी लगाते रहे।

संक्षिप्त समाचार

समस्तीपुर में दिल दहला देने वाला हादसा: झोपड़ी में लगी आग से दो मासूमों की मौत

समस्तीपुर: जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के भगवानपुर चकशेखू गांव में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक झोपड़ी में अचानक लगी आग में दो मासूम बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान तीन साल के अंकित कुमार और पांच साल की प्रीती कुमारी के रूप में हुई है। दोनों भाई-बहन अपने ननिहाल में रह रहे थे।

बिजली के स्पार्क से लगी आग, झोपड़ी में सो रहे थे बच्चे

परिवार के मुताबिक, हादसे के वक्त घर के बड़े सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे झोपड़ी में सो रहे थे। अचानक बिजली के तारों में स्पार्क हुआ, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि झोपड़ी कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दमकल टीम ने पाया आग पर काबू, लेकिन मासूमों को नहीं बचाया जा सका सूचना मिलते ही दलसिंहसराय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और झोपड़ी से बच्चों के शव निकाले। आग में घर के सारे सामान झ कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी चीजें झ भी जलकर राख हो गईं। शुरूआती अनुमान के अनुसार परिवार को हजारों रुपये की क्षति हुई है।

गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृत बच्चों के नाना भूखा सदा ने बताया कि जब हादसा हुआ, तब घर में सिर्फ दोनों बच्चे ही मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद चिंगारियों से ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा।

ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े.जन प्रगति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 2 लोगों की मौत; 4 घायल

Motihari बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में जन प्रगति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत दो लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि जन प्रगति पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार से जा था। शनिवार देर रात जलवाटोला स्थित राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या 27 पर एक खड़े ट्रक से तेज रफ़्तार कार टकरा गयी। इस घटना में जन प्रगति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार और केसरिया विधानसभा सीट से जन प्रगति पार्टी की संभावित उम्मीदवार ज्ञानती देवी की मौत हो गयी, जबकि चार अन्य घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बोले मांझी- ठऊअ व पीएम मोदी का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना

पटना: भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ (CEO) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने यह जानकारी साझा की है। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। '2027 तक भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था' मांझी ने कहा कि महागठबंधन, इंडी गठबंधन के लोगों के पास केवल एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा लेकिन एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के पास दूरदृष्टि और लोगों का समर्थन है... हम इसके लिए भारत के लोगों को बधाई देते हैं।

भारत ने जापान को छोड़ा पीछे- सीईओ

मांझी की यह टिप्पणी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला दिया। बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने यह भी बताया कि भारत अगले 2, 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी से आगे निकल सकता है। मैं जब बोल रहा हूँ, तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं जब बोल रहा हूँ, तब हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, और यह मेरा डेटा नहीं है। यह आईएमएफ डेटा है। भारत आज जापान से बड़ा है। सुब्रह्मण्यम ने कहा, अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे देश बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच-विचार पर टिके रहे तो यह 2, 2.5 से 3 साल की बात है; हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आईएमएफ की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अप्रैल संस्करण के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए नाममात्र जीडीपी लगभग 4,187.017 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह जापान की संभावित जीडीपी से थोड़ा अधिक है, जिसका अनुमान 4,186.431 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

अलीनगर में यादव पर बीजेपी तो ब्राह्मणों पर है RJD की नजर Bihar Election 2025

अलीनगर: अलीनगर में यादव पर बीजेपी तो ब्राह्मणों पर है RJD की नजर Bihar Election2025Alinagar Assembly Seat: अलीनगर विधानसभा सीट दरभंगा जिले में स्थित है.....2008 में परिसीमन के बाद अलीनगर विधानसभा अस्तित्व में आई थी। साल 2010 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही जीत हासिल की थी। 2015 में भी हुए चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जीत का सिलसिला कायम रखा था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मिश्री लाल यादव ने जीत का परचम लहरा दिया था। हालांकि 2025 में मिश्री लाल यादव विवादों के केंद्र में आ गए....मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को एक व्यक्ति पर हमले के मामले में कोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या इस बार बीजेपी मिश्री लाल यादव को टिकट देगी या नहीं।

मैं जमालपुर बोल रहा हूं रेल मंत्री जी, मुझे आखिर कब मिलेगा रेल निर्माण कारखाना का दर्जा ?

रहनुमाओं की रहनुमाई' देखिए कि देश को अब तक बिहार ने दिए सबसे अधिक रेल मंत्री

रंजीत कुमार विद्यार्थी

मुंगेर : एशिया प्रसिद्ध एवं बिहार का पहला रेल कारखाना जमालपुर का तीन दिन पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव निरीक्षण करने आए और उन्होंने 350 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुर रेल कारखाना के कायाकल्प की सौगात दी. लेकिन मुंगेर वासियों की ओर से पिछले 05 दशक से जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की मांग को कोई तवज्जो नहीं दिए जाने से जिले बासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. बताते चले की 17 वर्षों के बाद किसी केंद्रीय रेल मंत्री ने एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण किया. जिले वासियों को आशा और उम्मीद थी कि 05 दशकों से उठ रहे निर्माण कारखाना की मांग को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. रेल मंत्री ने जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की दिशा में कोई चर्चा तक अपने संबोधन में नहीं किया. जिस कारण जिले के लोगों को निराशा हाथ लगी. जिले के लोग अब कहने लगे हैं कि हम लोगों को पूरी आशा और उम्मीद थी कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई. इधर, एनडीए के विपक्षी दल राजद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाम दल तथा जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस कार्यक्रम को सिर्फ चुनावी कार्यक्रम करार दे रहे हैं. बताते चले की यहां के लोग जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की मांग को लेकर पिछले 05 दशक से धरना प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक लोगों का सपना साकार नहीं हो पाया है. इतना ही नहीं प्रत्येक लोकसभा चुनाव में जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिलाना चुनावी मुद्दा भी बनता रहा है और हरेक दल के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से वायदे भी करते है कि चुनाव जीतने के बाद इसे निर्माण

कारखाना का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 'रहनुमा'अपने वायदे को किसी सपने की तरह विसार देते हैं. जिसको लेकर जिले वासियों में रहनुमाओं के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है. वही, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगमन से पूर्व भाजपा - जदयू के नेता और कार्यकर्ता ढिंढोरा पीट रहे थे कि रेलमंत्री आएंगे और जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा प्रदान करेंगे. जो कि झूठा साबित हुआ. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार तथा रामविलास पास्वान और लालू यादव एक-एक बार केंद्रीय रेल मंत्री रहे, लेकिन एशिया प्रसिद्ध एवं बिहार का पहला रेल कारखाना जमालपुर को निर्माण कारखाना का दर्जा नहीं दिला पाए. देश को अब तक सबसे अधिक रेल मंत्री बिहार ने दिए, फिर भी जमालपुर को नहीं मिला निर्माण कारखाना का दर्जा बताते चले की देश को अब तक सबसे ज्यादा केंद्रीय रेल मंत्री बिहार ने दिए हैं. इसके बावजूद भी बिहार का सबसे पहला और एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा नहीं मिल पाया है. जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में 1862 ईस्वी में हुई थी. एक समय यहां 23, हजार से अधिक रेल कर्मी कार्यरत थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहां मात्र 05 से 06 हजार ही रेल कर्मी ही कार्यरत हैं. दिन - प्रतिदिन रेल कर्मियों की छटनी और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिस कारण जमालपुर रेल कारखाना के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडरा रहा है.

बिहार से केंद्र सरकार में कौन-कौन रहे रेल मंत्री

केंद्र सरकार में बिहार के अब तक कुल नौ रेल मंत्री रह चुके हैं और देश को सबसे अधिक रेल मंत्री बिहार ने ही हीं दिए हैं. इसके बावजूद भी बिहार का सबसे पहला और एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना की ओर इन रेल मंत्रियों की करमे इनायत नहीं हुई. केंद्र सरकार में बिहार के जो रेल मंत्री रहे हैं, उनमें बाबू जगजीवन राम (1962), राम शुभम सिंह (1969), ललित नारायण मिश्रा (1973), केदार पांडे (1982), जॉर्ज फर्नांडिस (1989), रामविलास पासवान (1996), नीतीश कुमार 1998 और 2001(दो बार), तथा लालू प्रसाद यादव (2004) शामिल है. बिहार से नीतीश कुमार केंद्र सरकार में दो बार रेल मंत्री रह चुके हैं. लोगों का कहना है कि अगर बिहार के इन नौ रेल मंत्रियों में से किसी एक ने भी अपनी करमें इनायत जमालपुर रेल कारखाना पर कर देते तो शायद एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना को बहुत पहले ही निर्माण कारखाना का दर्जा मिल गया होता. लेकिन, बिहार से आने वाले किसी रेल मंत्री ने ईमानदारी पूर्वक जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया. जिसका परिणाम है कि आज जमालपुर रेल कारखाना के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडरा रहा है.

सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन तेज करने का लिया गया निर्णय

मुंगेर विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए राशि का आवंटन मिलने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा शुरू.

जून माह में करो या मरो के तर्ज पर किया जाएगा आंदोलन

मनीष कुमार

नौवागढी (मुंगेर): मुंगेर सदर प्रखंड अंतर्गत नौवागढ़ी शिव मंदिर प्रांगण में सर्वदलीय संघर्ष समिति शाखा नौवागढ़ी(मुंगेर) की आवश्यक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता कामरेड राम अवतार पंडित एवं संचालन सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक ने किया। संयोजक श्री मंडल ने कहा कि आज की बैठक में पूर्व में की गई संघर्ष एवं भविष्य में नोवागढ़ी में विश्वविद्यालय भवन का निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण अति शीघ्र कैसे हो इस पर ही आने वाले वक्ता अपना - अपना विचार व्यक्त करें. बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा, मुंगेर के संरक्षक नरेश सिंह यादव ने कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय भवन

निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु बिहार सरकार ने आवंटन भी भेज दी है. फिर भी अभी तक भूमि अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाना समझ से परे है. अक्षय कुमार दास ने कहा कि नौवागढ़ी की जनता यह कहती है की जब नोवागढ़ी में विश्वविद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति मिल ही गई है तो संघर्ष करने से क्या लाभ. मो. शकील अहमद ने कहा बिना संघर्ष किये बिना इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार में कुछ नहीं मिलता. अतः हमें यथाशीघ्र विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए आंदोलन को और तेज करना चाहिए. मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा मुंगेर के संयोजक प्रो. विनय कुमार सुमन ने कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राशि आने के बावजूद भी जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण भूमि अधिग्रहण के कार्य की शुरूआत नहीं करना बेहद दुखद है। प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा मुंगेर एवं सर्वदलीय संघर्ष समिति,नोवागढ़ी बैठक में यह निर्णय ले की अगर जून माह तक भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो विवश होकर हमें करो या मरो के तर्ज पर पहले अनिश्चित कालीन आमरण अनशन करना चाहिए. इसके बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो हमें आत्मदाह करने के

लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रोफेसर सुमन के इस प्रस्ताव का उपस्थित सभी साथियों ने ध्वनि मत से पारित किया. बैठक को गीता साह, उपेंद्र मंडल, जयप्रकाश यादव अधिवक्ता, योगेंद्र यादव उर्फ योगी , बिहार फूले अंबेडकर विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणि कुमार बौद्ध, पवन रंजन, पंकज कुमार दास, निरंजन यादव ने भी संबोधित किया.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मृतक दोनों मजदूरों के परिजनों से की बातचीत

तेजस्वी यादव के निर्देश मुकेश यादव ने मृतक के परिजनों को दी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि

दिव्य दिनकर संवाददाता

मुंगेर : मुंगेर सदर सदर प्रखंड अंतर्गत मय पंचायत के करारी टोला तोफिर निवासी निरंजन यादव एवं मय निवासी प्रभु यादव जिनकी मृत्यु पिछले दिनों दिल्ली के पहाड़गंज में मजदूरी करने के क्रम में दीवार गिरने के कारण हो गई थी । मृतक के परिजनों को सांत्वना देने का निर्देश पूर्व उपमुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा मिलने पर मुंगेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहें अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव अपने समर्थकों के साथ मृतक के घर पहुंचे और मृतक के परिवार के लोगों से भेंट कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तेजस्वी यादव से बातचीत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दुख के इस घड़ी में मैं एवं राजद परिवार आपके साथ खड़ा है. पिछले दिनों मैं जब मुंगेर आया था तो रूट चार्ट में मय का नाम नहीं रहने के कारण मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मैं शीघ्र ही आपके दुख को बांटने के लिए मैं आपके घर पर आकर पूरे परिवार बालों से मिलूंगा। प्रतिपक्ष के नेता के निर्देश पर राजद परिवार की तरफ से पूर्व प्रत्याशी मुकेश यादव ने पीड़ित दोनों मृतक की पत्नी को 50-50 हजार रुपया देकर आंशिक रूप से मदद किया। स्वर्गीय प्रभु यादव की पत्नी से तेजस्वी के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें कर मृतक के परिवारों को दुख की इस घड़ी में सांत्वना देते हुए उन्हें हिम्मत से रहने की सलाह दी. इस अवसर पर मय पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार यादव, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रो.विनय कुमार सुमन, जिला राजद मुंगेर के प्रवक्ता सौरभ गुप्ता, राजद नेता संजय कुमार संजू, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

मुंगेर में तूल पकड़ने लगा दबंगों द्वारा स्कूल भवन तोड़कर रास्ता बनाने का मामला, आक्रोश

बरियारपुर प्रखंड के फुलकिया मध्य विद्यालय के भवन को तोड़कर दबंग बना रहें रास्ता

सत्ता संरक्षित दबंगो के आगे बेबस व लाजार दिख रही जिला प्रशासन और पुलिस

डीएम और एसपी ने कहा था: किसी कीमत पर नहीं बनेगा रास्ता, फिर भी बन रहा रस्ता

रंजीत विद्यार्थी

मुंगेर: मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय फूलकिया के स्कूल भवन को दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर काली मंदिर के नाम पर रास्ता बनाए जाने का मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है. विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए स्कूल भवन को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किए जाने में शामिल दबंगो की अविलंब गिरफ्तारी की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से की है साथ ही इन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अविलंब रास्ता निर्माण पर रोक नहीं लगाया गया तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा. जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और पुलिस की होगी. स्कूल भवन ध्वस्त करने वाले दबंगो की गिरफ्तारी तथा शिक्षा विभाग के डीपीओ की खामोशी पर कार्रवाई की मांग करने वालों में बिहार फूले अंबेडकर विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणि कुमार अकेला, राजद के प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव, पंकज कुमार यादव, मुंगेर जिला राजद के महासचिव संतोष कुमार यादव, मीडिया सेल के मंटू शर्मा, संजय पास्वान, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य सह बेगूसराय जिला प्रभारी मो.

साहब मलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता संजय केसरी, जन स्वराज विचार मंच के जिलाध्यक्ष संतोष सहाय, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव, मीडिया सेल के अध्यक्ष मनोज क्रांति, कांग्रेस पार्टी के जमालपुर नगर अध्यक्ष साई शंकर, आरटीआई कार्यकर्ता सह अधिवक्ता ओमप्रकाश पोद्दार, नौवागढी दक्षिणी पंचायत के पूर्व सरपंच सह राजद नेता सुनील भगत, नौवागढी क्षेत्रीय विकास मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार, लोकमंच(सामाजिक - सांस्कृतिक संस्था) के महासचिव विनय कुमार सुमन सहित आदि सामाजिक एवं राजनीति कार्यकताओं ने बयान जारी कर दबंगों द्वारा फुलकिया मध्य विद्यालय के भवन को जेसीबी मशीन से तोड़कर काली मंदिर के नाम पर रास्ता बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है. नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा है कि जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका आरती विश्वकर्मा के द्वारा स्थानीय बरियारपुर थाना में विद्यालय भवन तोड़ने को लेकर 06 दिन पूर्व प्राथमिकी दर्ज कराई गई,तो फिर किस स्थिति में रास्ता का निर्माण दबंगो के द्वारा किया जा रहा है. जोकि पुलिस एवं शिक्षा विभाग सहित जिला प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए काफी है. सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकताओं ने आगे कहा कि मीडिया में डीएम एवं एसपी का बयान आया था कि किसी भी कीमत पर रास्ता का निर्माण नहीं होगा और दबंगो की जांचों उपरांत गिरफ्तारी होगी. लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डीएम और एसपी के संज्ञान में स्कूल भवन दबंगो द्वारा ध्वस्त कर रास्ता निर्माण का मामला आने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है और ना ही रास्ता निर्माण पर कार्य पूर्ण रूप से रोका लगाया गया है. घटना के 06 दिन बाद भी डीपीओ द्वारा घटनास्थल का मुयायना नहीं किया जाना सवालों के घेरे में है. डीपीओ सिर्फ डीएम को अपनी रिपोर्ट भेजने की बात कह अपना पल्ला झाड़ने दिख रहे हैं. वहीं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मामले में खामोश है. शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की खामोशी और दबंग की दबंगई से अब यह सवाल उठने लगा है कि कहीं यह कार्य सत्ता संरक्षित दबंगो के द्वारा तो नहीं कराया जा रहा है. ऐसे बरियारपुर प्रखंड में सरेआम चर्चा है कि यह सब सारा खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा है. जिस कारण से अधिकारी से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण दबंगो के भय से मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी दबंग के आगे लाचार और बेबस दिख रहे हैं. जिस कारण ग्रामीणो एवं शिक्षा प्रेमियों में क्षेत्रीय रहनुमाओ और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ डीएम और एसपी सहित स्थानीय थाना पुलिस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है, जो किसी भी वक्त आंदोलन का रूप अख्तर कर सकता है। बरियारपुर प्रखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस्की जांच कर विद्यालय तोड़ने वाले पर उचित करवाई करने की मांग किया है। वही, बरियारपुर प्रखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजेश सुबन्धु, प्रखंड बीस सूत्री के सदस्य चंद्र दिवाकर शर्मा, जदयू नेता शैलेंद्र कुमार सिंह, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष देवकी नंदन सिंह, समाज सेवी शशि आनंद अलेबला, समाजसेवी विनय कुमार सिंह, आदि ने कड़ी करवाई करने की मांग शिक्षा विभाग के अपर सचिव तथा मुंगेर के आयुक्त से कराने की मांग किया है।

मीर कासिम किला का नाम बदले जाने की कबायद राजनीतिक साजिश : विनय कुमार सिंह

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सह संसद डॉ भीम सिंह का बयान दुर्भावनापूर्ण

ऐतिहासिक धरोहरों को सांप्रदायिक रंग देने की हो रही कोशिश

दिव्य दिनकर संवाददाता

मुंगेर : 'लोकमंच '(सामाजिक - सांस्कृतिक संस्था) के महासचिव विनय कुमार सिंह ने बयान जारी कर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संसद डॉ भीमराव सिंह के विवादित बयान की निंदा करते हुए कहा कि सांसद का बयान पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है।मुंगेर का ऐतिहासिक किला ' मीर कासिम ' मुगल नवाब ने बनवाया था जो मुंगेर की ऐतिहासिक पहचान है। क्या है? मीर कासिम किला का इतिहास - मीर कासिम 1760 से 1763तक बंगाल (बंगाल, बिहार,उड़ीसा) का नवाब था।वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब बना और उसने अपने ससुर मीर जाफर की जगह ली।मीर कासिम को अंग्रेजों के लिए प्लासी की लड़ाई जीतने में मीर जाफर की भूमिका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले समर्थन दिया था।मीर कासिम को 1760में बंगाल का नवाब बनाया गया,जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को पद से हटा दिया। मीर कासिम ने 1762में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी।ऐसा उन्होंने राज्य के मामलों को बेहतर बनाने और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया था डॉ भीम सिंह इस ऐतिहासिक किला का नाम बदलकर सम्राट जरासंध करने की मांग राज्य तथा केंद्र सरकार से की है जो कहीं से भी उचित नहीं है।भाजपा पूर्व से ही ऐतिहासिक महत्व के उन स्थानों के नामों को बदलने का प्रयास करते रही है जो किसी मुस्लिम के नाम पर है।ऐसा करना इतिहास के साथ क्रूर मजाक है।इससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा होगा,जो कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं है।

न्यायालय ने फर्स्ट गेम्स को भेजे गए 5,712 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर रोक लगाई: पेटीएम

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाले रियल मनी गेमिंग मंच फर्स्ट गेम्स को भेजे गए 5,712 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर रोक लगा दी है। पेटीएम ब्रांड नाम के तहत कारोबार करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, नयी दिल्ली ने अप्रैल में फर्स्ट गेम्स को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया, फर्स्ट गेम्स ने हमें 24 मई, 2025 को सुबह 10:44 बजे (आईएसटी) बताया कि उक्त कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली फर्स्ट गेम्स की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 मई, 2025 को एससीएन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वन97 कम्युनिकेशंस ने कहा कि कर का मामला एक उद्योग-व्यापी मुद्दा है और फर्स्ट गेम्स तक सीमित नहीं है। इस मामले की सुनवाई न्यायालय कर रहा है।

जेके सीमेंट का मुनाफा चौथी तिमाही में 64.4 प्रतिशत बढ़कर 361.3 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली। जेके सीमेंट लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 64.5 प्रतिशत बढ़कर 361.33 करोड़ रुपये हो गया।जेके सीमेंट लिमिटेड (जेकेसीएल) ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 219.68 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। मार्च तिमाही में परिचालन राजस्व 15.3 प्रतिशत बढ़कर 3,581.18 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,105.77 करोड़ रुपये था। जेकेसीएल का कुल खर्च मार्च तिमाही में 3,092.04 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 9.8 फीसदी ज्यादा है।

उप्र सरकार का 2026-27 तक 347 नयी टीएचआर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 तक राज्य में 347 नई टीएचआर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान में कहा गया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार कुपोषण के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर रही है। इस समय 43 जिलों में 204 'टेक होम राशन' (टीएचआर) इकाइयों से 288 परियोजनाओं को आपूर्ति हो रही है और अब 2026-27 तक 347 नई टीएचआर इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 273.50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित होगा। बयान के अनुसार योजना के तहत विकेंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की गई है, जिसके लिए कुल 273.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संतकबीर नगर, अंबेडकरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बांदा, इटावा, प्रतापगढ़, ललितपुर, औरैया और महोबा जैसे जनपदों ने शत-प्रतिशत भुगतान पूरा कर लिया है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

'राइजिंग नॉर्थ ईस्ट' निवेशक सम्मेलन में 4.18 लाख करोड़ रुपये के करार की घोषणा: सिंधिया

ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली में चल रहे 'राइजिंग नॉर्थ ईस्ट' निवेशक सम्मेलन 2025 में 4.18 लाख करोड़ रुपये के करार की घोषणा की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में स्थापित करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों तथा नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। सिंधिया ने संवाददाताओं को बताया, पहली बार पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और इंदौर जैसे शहरों में रोड शो आयोजित किए गए। विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ बैठकें की गईं।

जापान को पछाड़ भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगले तीन वर्षों में जर्मनी से होगा आगे

एजेंसी

नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। सुब्रह्मण्यम ने 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं जब बोल रहा हूं, तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हैं और यह मेरा डेटा नहीं है। यह आईएमएफ का डेटा है। आज भारत जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं और जो योजना बनाई जा रही है, अगर हम उसी पर टिके रहते हैं, तो भारत

अगले 2, 2.5 से 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं, जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है और इस दौरान जीडीपी का आकार 5,069.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं, 2028 तक भारत की जीडीपी का आकार 5,584.476 अरब डॉलर होगा, जबकि इस दौरान जर्मनी की जीडीपी का आकार 5,251.928 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक, 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं, चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की जीडीपी वृद्धि इस साल 1.8 प्रतिशत तक धीमी होने की उम्मीद है, जो 2026 1.7 प्रतिशत तक रह जाएगी। वहीं, यूरोप की वृद्धि दर 2025 में मात्र 0.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, 2026 में इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी और यह 1.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर पड़े रहे।तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर रहा। वैश्विक स्तर पर साप्ताहांत पर अमेरिकी क्रूड 0.92 प्रतिशत उबलकर 61.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह लंदन ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत की तेजी लेकर 65.03 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

एलआईसी ने 24 घंटे में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बड़ी उपल्बिध हासिल की है। कंपनी ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (जीडब्ल्यूआर) का खिताब हासिल किया है। बीमा कंपनी के एजेंटों ने 20 जनवरी, 2025 को भारत में रिकॉर्ड 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां बेचीं है। जीवन बीमा कंपनी ने एक बयान में बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि उसने 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब जीता है। एलआईसी के एजेंटों ने 20 जनवरी, 2025 को पूरे भारत में रिकॉर्ड 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां बेचीं। जीवन बीमा कंपनी ने कहा कि 20 जनवरी, 2025 को एलआईसी के कुल 4,52,839 एजेंटों ने पूरे भारत में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां सफलतापूर्वक पूरी कीं और जारी कीं। इस शानदार प्रयास ने 24 घंटे की अवधि के भीतर जीवन

बीमा उद्योग में एजेंट उत्पादकता के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। जीवन बीमा पॉलिसियों की यह रिकॉर्ड बिक्री प्रत्येक एजेंट से मैड मिलियन डे यानी 20 जनवरी, 2025 को कम से कम एक पॉलिसी पूरी करने की अपील का हिस्सा थी। कंपनी की यह उपलब्धि 24 घंटे की अवधि के भीतर जीवन बीमा उद्योग में एजेंट उत्पादकता के लिए एक नया वैश्विक बेंचमार्क है। एलआईसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि यह उपलब्धि अपने ग्राहकों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के अपने मिशन के प्रति निगम की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और चीन के पीएम ने की टैरिफ पर चर्चा, मलयेशिया ने कहा- हम एकजुट हों

एजेंसी

बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने रविवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की और अमेरिका के वैश्विक व्यापार युद्ध तथा आर्थिक वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियों के दौरान व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। ली दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पर शनिवार दोपहर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। यह इस साल उनकी पहली विदेश यात्रा का पहला पड़ाव था। इंडोनेशिया और चीन 20 प्रमुख विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं व ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ली रविवार शाम को इंडोनेशिया-चीन व्यापार स्वागत समारोह में अपने संबोधन के लिए 60 प्रमुख चीनी व्यवसायियों को अपने साथ लाए। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती बाहरी चुनौतियों के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था ने इस साल तेजी से विकास हासिल किया है। ली ने इस कार्यक्रम में कहा, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गतिरोध की स्थिति

में है, एकतरफावाद और संरक्षणवाद बढ़ रहा है, धमकाने वाला व्यवहार बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में सुबियांटो भी मौजूद थे।

ली ने कहा कि इस वर्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ है, जिसे एशियाई और अफ्रीकी देशों द्वारा इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित किया गया था, जब सात दशक से अधिक समय पहले विश्व एक ऐतिहासिक चौराहे पर था। ली ने कहा कि एकजुटता, मैत्री और सहयोग की बांडुंग भावना ने वैश्विक दक्षिण देशों की एकता और सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।ली ने कहा, सात दशक से भी अधिक समय बाद, दुनिया एक बार फिर महत्वपूर्ण चौराहे पर है।उन्होंने सभी देशों से बातचीत और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के माध्यम से मतभेदों को सुलझाते हुए साझा आधार तलाशने का आह्वान किया। मलेशिया ने कहा- अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए एकजुट रहना चाहिए मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने रविवार को कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लानी चाहिए।

ईपीएफ पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी है। इससे ईपीएफओ अपने 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज को जमा कर सकेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दर पर अपनी सहमति दे दी है। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को ईपीएफओ को इस बारे में एक पत्र भेजा है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25 फीसदी की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। ये इससे पिछले वित्त वर्ष में दिये गये ब्याज दर के

बराबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया था, जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई दर के बराबर है। 2024-25 के लिए स्वीकृत ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा गया था। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता का 12 फीसदी राशि ईपीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता का 12 फीसदी जमा करती है। कंपनी के 12 फीसदी हिस्से में से 3.67 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है, जबकि बाकी 8.33 फीसदी धनराशि पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं, कर्मचारी के हिस्से का सारा पैसा ईपीएफ अकाउंट में जाता है।

दरअसल 2022 में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से ज्यादा के निचले स्तर 8.10 फीसदी कर दिया था। वित्त वर्ष 2020-21 में यह ब्याज दर 8.5 फीसदी थी। ईपीएफ पर 8.10 फीसदी ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, उस वक्त ये दर सिर्फ आठ फीसदी थी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर सात साल के निचले स्तर 8.5 फीसदी कर दिया था, जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत था।

जिंसों में टिकाव

एजेंसी

नई दिल्ली। स्थानीय स्तर पर मांग कमजोर रहने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिसों के भाव स्थिर रहे। इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और पिछले स्तर पर पड़े रहे।

गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी और गुड़ के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टीके रहे।

दाल-दलहन: दाल-दलहन के बाजार में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और अरहर दाल में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अनाज : अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान गेहूं और चावल के दाम पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर पड़े रहे।

'जातिगत जनगणना विभाजनकारी नहीं', एनसीएससी के अध्यक्ष बोले- आंकड़ों से सामाजिक न्याय होगा मजबूत

एजेंसी

मुंबई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने जातिगत गणना से समाज में खाई पैदा होने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि एकत्र किए गए आंकड़े नीतिगत निर्णय लेने में आधार के रूप में काम आएंगे। इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। आयोग के मुखिया ने कहा कि इससे हाशिए पर पड़े पिछड़े समुदायों के उत्थान में मदद मिलेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किए जाने का मकवाना ने स्वागत कहा है। उन्होंने कहा कि 2011 से उलट इस बार, ÷निश्चित आंकड़े उपलब्ध होंगे÷ जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक आनुपातिक पहुंच सुनिश्चित को सकेगी। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करवाई थी, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने की पहली कोशिश थी। हालांकि, 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़े कभी भी पूरी तरह से जारी या उपयोग नहीं किए गए। जातिगत जनगणना से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होने की चिंताओं को खारिज करते हुए मकवाना ने कहा, 'इससे जाति के आधार पर कोई विभाजन पैदा नहीं होगा। बल्कि, इससे सामाजिक न्याय मजबूत होगा। उन्होंने कहा, यह पिछड़ी जातियों का उत्थान करेगा और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बाबासाहेब अंबेडकर के सपने के सभी तीन पहलुओं -सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक- को मजबूत करेगा। एनसीएससी अध्यक्ष ने कहा कि जाति जनगणना से सटीक आंकड़े मिलेंगे। इससे मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को बेहतर तरीके सुविधाएं दी जा सकेंगी। उन्होंने कहा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो लोग वंचित रह गए हैं, उन्हें अंततः उनका हक मिले। मकवाना ने साफ किया कि एनसीएससी सीधे तौर पर गणना प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी।

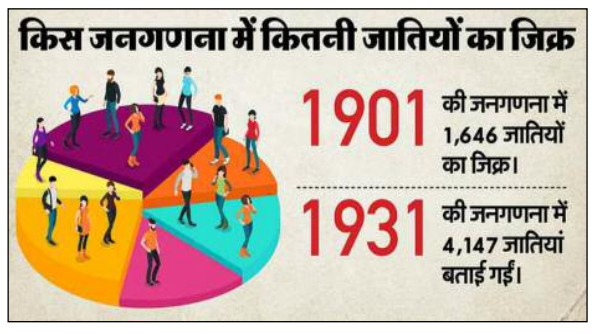

तेलंगाना का 2047 तक जीडीपी में आठ प्रतिशत योगदान का लक्ष्य : मुख्यमंत्री रेड्डी

नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ प्रतिशत का योगदान करना है। उन्होंने छह प्रमुख महानगरीय शहरों को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य दल बनाने का प्रस्ताव भी रखा। रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में कहा कि तेलंगाना देश की आजादी की शताब्दी के लिए सरकार के लक्ष्य ÷विकसित भारत को हासिल करने की दिशा में जारी प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य वर्तमान में भारत की जीडीपी में लगभग 2.5 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि इसकी आबादी 2.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, ÷तेलंगाना इस

जिम्मेदारी को निभाने और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने छह महानगरों- मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों के अधीन एक राष्ट्रीय कार्य दल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये छह शहर आर्थिक वृद्धि, नवाचार और रोजगार सृजन के इंजन के रूप में काम करते हैं।

एनटीपीसी का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़कर 7,897 करोड़ रुपये पर

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ लगभग 22 प्रतिशत बढ़कर 7,897.14 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में 6,490.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान एनटीपीसी की परिचालन आय सालाना आधार पर 47,628.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 49,833.70 करोड़ रुपये हो गई। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 23,953.15 करोड़ रुपये हो गया, जो 2023-24 में 21,332.45 करोड़ रुपये था। इस दौरान परिचालन आय भी 1,78,524.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,88,138.06 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2024-25 के लिए 33.50 प्रतिशत (3.35 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है।

पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की, एफटीए पर हुई चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं की एक महीने के भीतर दूसरी मुलाकात थी, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा की गई। गोयल ने इस महीने की शुरुआत में अपने यूरोपीय संघ समकक्ष के साथ बैठक की थी। यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एक्स' पोस्ट पर इस मुलाकात और बातचीत की जानकारी दी है। यूरोपीय संघ के अधिकारी मारोस सेफकोविक ने एक्स पोस्ट के माध्यम से कहा, अपने मित्र और समकक्ष पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। आइए, हम कड़ी मेहनत और स्पष्ट फोकस के साथ गति बनाए रखें। मैं जल्द ही हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वहीं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मारोस सेफकोविक

के पोस्ट के जवाब में 'एक्स' पर लिखा है, मेरे मित्र, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। हम भारत और यूरोपीय संघ की साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए, हम इस गति को जारी रखें! अमेरिका के दौरे पर गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 23 मई को वाशिंगटन से ब्रुसेल्स पहुंचे, जबकि भारत के मुख्य वार्ताकार एल. सत्य श्रीनिवास और उनकी टीम भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता

गोयल ने इस महीने की शुरुआत में अपने यूरोपीय संघ समकक्ष के साथ बैठक की थी।

और यूरोपीय संघ की साझा समृद्धि के लिए पहले से ही यूरोपीय संघ मुख्यालय में मौजूद हैं। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब दोनों पक्ष जुलाई तक अर्ली हार्वेस्ट व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के अनुसार ईयू-भारत व्यापार वार्ता गति पकड़ रही है, दोनों पक्षों का लक्ष्य 2025 के अंत तक एक समझौते को पूरा करना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत में तेजी लाने के लिए डच समर्थन भी मांगा, जिसे भारत 2025 के अंत तक पूरा करने की उम्मीद करता है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने हाल ही में 16 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्यारहवें दौर की वार्ता पूरी की है।

प्रभास को छोड़ अल्लू अर्जुन की फिल्म में सेट हो गईं

दीपिका पादुकोण

इतने करोड़ में डील हुई फाइनल!

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म काफी चर्चा बटोर रहा है. एटली के साथ एक्टर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जाह्नवी कपूर के शामिल होने की खबर है. प्रेग्नेंसी के बाद से एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार हो चुकी हैं. हाल ही में आ रही खबर में ये सामने आ रहा है कि दीपिका ने इस फिल्म को ऑफिशियल साइन कर दिया है.दीपिका पादुकोण की जब से फिल्मों में वापसी की खबर सामने आई है, तभी से उनका नाम कई सारे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है. फिलहाल एक्ट्रेस का नाम अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है, फेमस फिल्ममेकर एटली की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल AA22&A6रखा गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म में 3 एक्ट्रेस शामिल होंगी. खबरों में बताया जा रहा है कि कई महीनों से दीपिका और एटली की इस फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी.

कितनी ले रही हैं फीस ?

700 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में दीपिका की फीस को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है. मिड-डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए फीस के तौर पर ले रही हैं. अब लोग जल्द ही इस फिल्म का फील्ड पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, पहले वो शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की शूटिंग पूरी करेंगी. किंग साल 2026 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं.

स्पिरिट में भी आया था नाम

हालांकि, शाहरुख और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के साथ ही साथ एक्ट्रेस का नाम प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में भी जोड़ा जा रहा था. लेकिन, बाद में खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म से दीपिका बाहर आ चुकी हैं. एटली के साथ दीपिका की ये दूसरी फिल्म होगी. इससे पहले दोनों ने 'जवान' में साथ काम किया था.हालांकि, फिल्मों में दीपिका की वापसी के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के लिए कुछ वक्त तक फिल्मों से दूरी बना ली थी.

15 साल की उम्र में खरीदा घर, अब ये है मोहब्बतें की इस एक्ट्रेस ने बोर्ड एक्जाम में कमाल कर दिया

फिल्म और टीवी की दुनिया में कई सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग की हर तरफ प्रशंसा भी देखने को मिल रही है. ऐसा ही किया है एक्ट्रेस रुहानिका धवन ने. उन्होंने पहले तो ये है मोहब्बतें में यंग रूही भल्ला का रोल प्ले कर के सभी को खूब एंटरटेन किया. लेकिन इसी के साथ एक्ट्रेस ने पढ़ाई में भी मन लगाया. उनके 12ह्लद्ध का रिजल्ट आ गया है और एक्ट्रेस काफी अच्छे नंबर्स से पास हुई हैं. उन्होंने 12th के बोर्ड एग्जाम में 91 पर्सेंट हासिल किए हैं. इस बात से वे काफी खुश भी हैं.

किसी भी चाइल्ड एक्टर के लिए अपने काम के साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है. एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि अपने बिजी शेड्यूल के बीच कैसे उन्होंने वक्त निकालकर बोर्ड की तैयारी की और अच्छे नंबर लाने में भी सफल हुईं. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान कहा- मैं बोर्ड में 91 पर्सेंट नंबर लाकर काफी खुश महसूस कर रही हूं. मैंने वाकई में बहुत मेहनत की. मैंने 3 साल के लिए अपना एक्टिंग करियर ताक पर रख दिया था ताकि मैं पढ़ाई पर ध्यान लगा सकूं. अब मुझे लगता है कि मेरा ऐसा करना सफल हुआ. मेरे पैरेंट्स को भी मुझपर पूरा भरोसा था कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगी और मैंने उन्हें सही साबित कर दिया. मेरी उम्र के दूसरे एक्टर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं लेकिन मैंने पढ़ाई को चुना.

आगे क्या करेंगी रुहानिका ?

रुहानिका ने अपने आगे के प्लान्स के बारे में भी बातें कीं. उन्होंने बताया कि- मैं अब महाराष्ट्र के कई अच्छे कॉलेज के इंटरेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूं. अगर मेरे कॉलेज का शेड्यूल फ्लेक्सिबल होगा तो मैं एक बार फिर से अपने एक्टिंग करियर की ओर अपना फोकस कर पाऊंगी'. मतलब साफ है कि एक्ट्रेस अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यू रखना चाहती हैं लेकिन वे एक्टिंग से भी पूरी तरह से तौबा नहीं करना चाहती हैं. वे फिलहाल 17 साल की हैं और अपने करियर को लेकर काफी आशावादी हैं.

15 की उम्र में खरीदा था घर

रुहानिका अभी भले ही 17 साल की हैं लेकिन इस उम्र में ही वे काफी सक्सेसफुल भी हो गई हैं. एक्ट्रेस ने 15 साल की नाजुक उम्र में अपना पहला घर भी खरीद लिया था. इस बात की खुशी जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- अपनी मेहनत के पैसे से घर बनाना मेरे लिए अनबिलीवेबल है.

जब बेस्टफ्रेंड के पति को शाहरुख खान ने जड़ दिया था थप्पड़, 150 करोड़ के नुकसान पर उड़ाया था मजाक

शाहरुख खान फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हैं, साथ ही साथ उनकी फैन फॉलोइंग भी दुनियाभर में काफी ज्यादा है. शाहरुख फिल्मी दुनिया के उन सितारों में से हैं, जिनको लेकर काफी कम नेगेटिव खबरें आती हैं. साथ ही इंडस्ट्री में लोगों के साथ भी एक्टर के काफी अच्छे कनेक्शन भी हैं. हालांकि, एक बार एक्टर उस वक्त चर्चा में बन गए थे, जिस वक्त उन्होंने अपनी बेस्टफ्रेंड के पति को एक भरी पार्टी में थप्पड़ जड़ दिया था.शाहरुख खान के रिश्ते कई लोगों के साथ अच्छे हैं, जिनमें से एक फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हैं. फराह के साथ शाहरुख ने कई कमाल की फिल्में भी दी हैं, साथ ही दोनों का बॉन्ड आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब उन्होंने उनके पति शिरीष कुंदर को थप्पड़ जड़ दिया था. शिरीष कुंदर ने एडिटर के तौर पर इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था. हालांकि, शाहरुख खान से उनका रिश्ता काफी वक्त से अच्छा नहीं रहा है.

फिल्म की थी ऑफर

दरअसल, दोनों के रिश्ते के बीच तकरार एक फिल्म की वजह से आई थी. शिरीष ने शाहरुख खान को एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन जब एक्टर ने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उन्हें ये खास पसंद नहीं आई. जिसके बाद शाहरुख ने शिरीष को स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कहा था. हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस मामले में वक्त काफी ज्यादा आगे निकल गया और फिर उन्होंने फिल्म में शाहरुख की जगह अक्षय कुमार को कास्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने तीस मार खां बनाया.

'रा वन' पर किया था कमेंट

वहीं बाद में शाहरुख खान फिल्म 'रा वन' में नजर आए थे, जिसकी रिलीज से पहले ही शिरीष ने इसे लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया था. शिरीष ने लिखा था कि 'रा वन' सब कुछ कर सकता है कि सिवाय फैंस को एंटरटेन करने के. इसके अलावा उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में फिल्म के बजट पर बात करते हुए लिखा था कि 150 करोड़ के पटाखे के फुस्स. इन सबी नेगेटिव ट्वीट्स पर एक्टर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था.

पार्टी में जड़ा था थप्पड़

हालांकि, बाद में शिरीष और शाहरुख की मुलाकात संजय दत्त की फिल्म 'अग्निपथ' की सक्सेस पार्टी के दौरान हुई. बताया गया कि इस दौरान भी शिरीष ने 'रा वन' को लेकर कई सारे कमेंट किए. जिसके बाद शाहरुख ने गुस्से में आकर शिरीष को सभी के सामने थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि, इस मामले को लेकर फराह ने सभी चीजों को गलत ठहराया था, लेकिन शिरीष ने कहा था कि उन पर मुक्के भी बरसाए गए हैं. लेकिन, कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने कमेंट के लिए एक्टर से माफी मांग ली थी.

पिता हीरा व्यापारी, भाई US में डॉक्टर...मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एंबेसडर बनीं

तमन्ना भाटिया

को कितना जानते हैं आप?

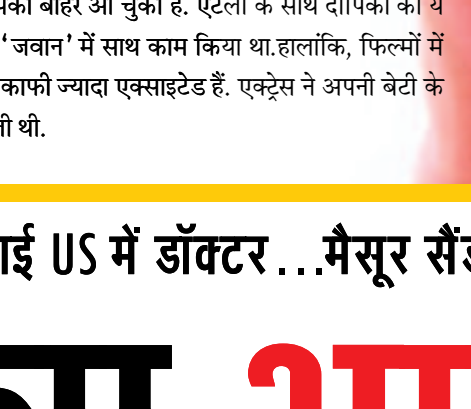

कर्नाटक सरकार ने साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. तमन्ना 2 साल के लिए 6.2 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं. हालांकि, उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने पर बवाल भी मचा हुआ है. चलिए इस मामले के बीच आपको तमन्ना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जो शायद ही आप जानते हों.तमन्ना का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम संतोष भाटिया है, जो एक हीरा व्यापारी हैं. उनकी मां का नाम रजनी भाटिया है. एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई लिखाई मुंबई से की है. उन्होंने मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट से अपनी स्कूलिंग की. वहीं उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज से डिस्टेंस में आर्ट्स में बैचलर डिग्री ली है.

तमन्ना भाटिया की फिल्मी करियर

तमन्ना के एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम आनंद भाटिया है. वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और अमेरिका में रहते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि तमन्ना ने अपना फिल्मी करियर साउथ फिल्मों से शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने साल 2005 में बॉलीवुड से ही डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म 'चांद से रौशन चेहरा' थी. उसी साल उन्होंने 'श्री' नाम की फिल्म से तेलुगु सिनेमा में भी कदम रखा था और फिर 2006 में 'केड़ी' नाम की फिल्म से उन्होंने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था.

डेब्यू के बाद तमन्ना ने ढेरों फिल्मों में काम किया, लेकिन वो लोगों की नजरों में साल 2015 में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' से आईं. तमन्ना आज के समय में बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. साल 2024 में रिलीज हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' में उन्होंने आइम नंबर किया था. 'आज की रात' गाने में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था. उसके बाद से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगीं.

तमन्ना को ही क्यों बनाया ब्रांड एंबेसडर ?

बहरहाल, चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर तमन्ना को ही क्यों ब्रांड एंबेसडर बनाया गया. रश्मिका मंदाना, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, पूजा हेगड़े के होते हुए तमन्ना को ही ब्रांड एंबेसडर के तौर पर क्यों लिया गया. इस सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार में मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि रश्मिका ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया था. पूजा और कियारा को लेना भी पॉसिबल नहीं हुआ और दीपिका बजट में नहीं थीं.

इन सबके नामों पर विचार हुआ था, लेकिन जब मुमकिन नहीं हुआ तो तमन्ना को लिया गया. उन्होंने ये भी कहा कि तमन्ना के इंस्टाग्राम पर 2.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो इसके लिए सही हैं.